

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 15 ■ अंक - 316 ■ अम्बिकापुर, रविवार 15 दिसम्बर 2024 पृष्ठ - 8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

हथियारबंद गिरोह अमेरा खदान में धावा बोला

ट्रकों से कट्टे की नोक पर डीजल निकाला



छ.ग.फ्रंटलाइन लखनपुर। थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात अमेरा खदान में हथियारबंद गिरोह ने कट्टे की नोक पर

बलपूर्वक 7 ट्रकों से डीजल चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना को लेकर ट्रक चालक भयभीत हैं। शनिवार को ट्रक चालकों ने लखनपुर थाने पहुंच कर मामले की शिकायत की है। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर जिले की एक ही कंपनी की सात ट्रकों क्रमांक सीजी 10 बीएच 3800, सीजी 10 बीएच 6100, सीजी 10 बीएच 6500, सीजी 15 डीआर 9500, सीजी 13 एफ 1507, सीजी 31 ए 8130, सीजी 13 एएफ 1522 वाहन से 13 व 14 दिसंबर की दरम्यानी रात अमेरा खदान, कांटा घर और बूम बैरियर के पास खड़े थे। इसी दौरान 20 से 22 की संख्या में हथियार बंद बदमाश पहुंचे और कट्टे की नोक पर बलपूर्वक 7 ट्रकों से रस्सा, तिरपाल और डीजल चोरी की घटना को अंजाम दिए। घटना के बाद से ट्रक चालक में भय का माहौल है। 14 दिसंबर, शनिवार को लखनपुर थाने में घटना की जानकारी दी गई है। लिफ्टरों और ट्रक चालकों ने बताया कि विगत 9 माह से डीजल चोरी की घटनाएं जारी हैं, जिससे ट्रक मालिकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस हथियार बंद गिरोह को पकड़ने में कब तक सफल हो पाती है।

धान मिसाई के दौरान ट्रैक्टर और थ्रेसर में लगी आग

छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। बलरामपुर थाना क्षेत्र के बड़कीमहरी गांव में धान मिसाई के दौरान ट्रैक्टर और थ्रेसर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि किसान कृष्ण सिंह के यहां धान की मिसाई के दौरान ट्रैक्टर के इंजन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग थ्रेसर और धान के खलिहान तक



फैल गई। इससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। हालांकि, आग लगने से ट्रैक्टर और थ्रेसर पूरी तरह जल चुका है। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन किसान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

कृषि महाविद्यालय के हॉस्टल में बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र फांसी लगाकर खुदकुशी किया

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कृषि महाविद्यालय में अध्ययनरत द्वितीय वर्ष के छात्र ने अज्ञात कारणों से हॉस्टल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से सहपाठी छात्रों में शोक का माहौल है। देर शाम छात्र के स्वजन अंबिकापुर पहुंचे और माहौल गमगीन हो गया। रविवार को पुलिस छात्र के शव का पोस्टमार्टम कराएगी। जानकारी के मुताबिक मुंगेली थाना क्षेत्र के ग्राम डांडगांव का विवेक अनन्त पिता सतानन अनन्त 18 वर्ष, अंबिकापुर से लगे ग्राम अजिरमा में स्थित राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय में बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र था। छात्र कॉलेज के हॉस्टल क्रमांक-2 के कमरा नंबर 36 में एक अन्य सहपाठी छात्र के साथ रहता था। घटना दिवस छात्र कमरे में अकेले था, साथ में रहने वाला सहपाठी छुट्टी में गया है।



बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात को विवेक अनन्त कॉलेज में पढ़ने वाले अन्य सहपाठियों के साथ रोजाना की भांति मिला और रात में खाना खाने के बाद सोने के लिए चले गया था। सुबह छह बजे तक वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो हॉस्टल में रहने वाले अन्य छात्रों ने सोचा सो रहा होगा इसलिए उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। नौ बजे भी जब विवेक के कमरे का दरवाजा नहीं खुला, तो वे उसे उठाने का प्रयास करने लगे। दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब अंदर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई तो लड़के पीछे की खिड़की से झांककर देखे, तो विवेक का फांसी के फंदे पर लटका नजर आया। आननफानन में इसकी जानकारी हॉस्टल इंचार्ज व कृषि महाविद्यालय के डीन को दी गई। दरवाजे को बलपूर्वक तोड़कर अंदर गए तो उसका सांस चल रहा था। छात्र को फांसी के फंदे से उतार कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लाया गया, यहाँ जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्र ने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसका पता नहीं चल पाया है। कुछ छात्रों को

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री अमित शाह
माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार

दुकान के सामने खड़ी स्कूटी में अलसुबह अज्ञात लड़की आग लगाई

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के घुटरापारा में दुकान के बाहर खड़ी स्कूटी वाहन को एक युवती ने आग के हवाले कर दिया। आग लगाने के पहले वह एक स्कूटी को किनारे की, बाद में दूसरे स्कूटी वाहन में आग लगा दी। कुछ ही देर में स्कूटी वाहन जलकर खाक हो गई, वहीं पास ही खड़ी दूसरी स्कूटी वाहन का भी वाह्य हिस्सा आग के ताप से खुरी तरह से झुलस गया है। युवती की हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई है। जानकारी के मुताबिक मायापुर, घुटरापारा में कलीम अंसारी का एस्के सेनेटरी एंड हार्डवेयर नामक दुकान है। दुकान बंद होने के बाद यहां आसपास के लोग घर में जगह नहीं होने के कारण अपनी दोपहिया वाहनों को खड़ा कर देते हैं। सुबह लगभग 5 बजे कलीम अंसारी को मोबाइल फोन में सूचना मिली कि उनके दुकान के सामने खड़ी स्कूटी में आग लगा है। जब वे मौके पर पहुंचे, तो पड़ोस में रहने वाली अनु शर्मा का इलेक्ट्रिक स्कूटी जलकर खाक हो गया था। पास में खड़ी एक अन्य स्कूटी का बाहरी हिस्सा आग के ताप से झुलस गया था। सीसीटीवी का अवलोकन करने पर पता चला कि एक लड़की दुकान के सामने खड़ी स्कूटी के पास पहुंचने के बाद एक स्कूटी को किनारे करने के बाद उसमें खड़ी होकर उछलकूद करने लगी, बाद में अनु शर्मा के स्कूटी वाहन में माचिस जलाकर आग लगा दी। ऐसे में दुकान संचालक ने अनु शर्मा से दुश्मनी की भावना से स्कूटी को आग के हवाले करने का अंदेश व्यक्त किया है। वहीं अनु शर्मा का कहना है कि वह स्कूटी में आग लगाने वाली लड़की को नहीं पहचानती है।



दिनभर शोरूम में एकाउंटेंट के काम में व्यस्त रहती है, जिस कारण किसी से उसका ज्यादा बातचीत भी नहीं होता है। बहरहाल घटना की जानकारी कोतवाली थाना में दी गई है, जिस पर पुलिस आग लगाने वाली युवती के पतासाजी में लगी है।

सुशासन पर्व के दूसरे दिन रंगोली, मेहंदी, पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ सरकार के गठन के एक वर्ष और सुशासन पर्व पर द्वितीय दिवस रंगोली, मेहंदी, पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन इंजीनियरिंग कॉलेज में 14 दिसम्बर को किया गया। संस्था के प्राचार्य डॉ. राम नारायण खरे ने उपस्थित जनों से राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के पीएचडी, एमटेक एवं बीटेक के छात्र-छात्राएं, एनएसएस के स्वयं सेवक, रेड रिबन, स्वीप कैंपस एग्जिबिट, कर्मचारी, सभी विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापकों ने बड़-बड़कर हिस्सा लिया। मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम

संजय निपाद बीटेक पंचम सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, द्वितीय स्थान ईशिका तिवारी बीटेक तृतीय सेमेस्टर माइनिंग इंजीनियरिंग एवं तृतीय स्थान सोमो सोनी बीटेक तृतीय सेमेस्टर माइनिंग इंजीनियरिंग ने प्राप्त किया। पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान दीपक चंद्रवंशी



बीटेक पंचम सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस, द्वितीय स्थान अमित कुमार महंत बीटेक पंचम सेमेस्टर मेकेनिकल इंजीनियरिंग एवं तृतीय स्थान विकास कुमार डनसेना बीटेक पंचम सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ने प्राप्त किया। रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्रिया राठोर बीटेक पंचम सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस, द्वितीय स्थान इंदु राजवाड़े बीटेक पंचम सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग ने प्राप्त किया। तीनों प्रतियोगिताओं में 21 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों, कर्मचारी एवं प्राध्यापकों द्वारा नागरिकों को राज्य सरकार की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं, गतिविधियों का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम समन्वयक पूजा पात्रे एवं जासमीन मित्र, सहायक प्राध्यापक थे।

कहना है कि दो दिन से विवेक कुछ परेशान नजर आ रहा था, लेकिन दोस्तों के साथ सामान्य व्यवहार करता था। घटना की जानकारी मिलने पर महाविद्यालय के छात्रों का हुजूम अस्पताल में जमा हो गया। कृषि महाविद्यालय के डीन सहित अन्य प्राध्यापक भी अस्पताल पहुंचे। घटना की जानकारी अस्पताल के पुलिस सहायता केन्द्र में दी गई, पुलिस ने मृतक के शव को मर्चुरी में रखवाया है।

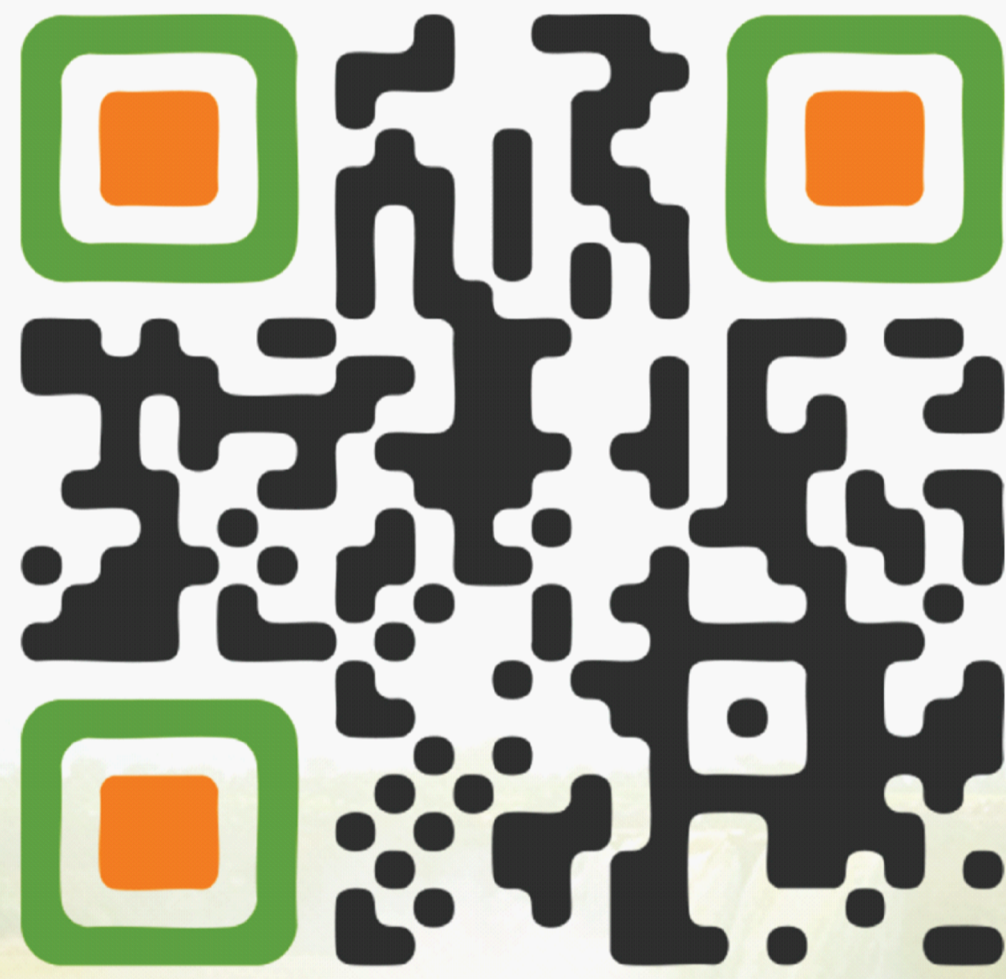
आर.ओ. नं.-42449/14

C
M
Y
K

मैं हूँ बदलता



बस्तर



नया बस्तर देखने के लिए स्कैन करें



श्री अमित शाह
माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़, संवाद-42449/14



उपासना स्थल कानून का समी करें सम्मान

उपासना स्थलों से संबंधित मामलों पर सुनावाई या कोई आदेश पारित न करने की हिदायत अदालतों को देकर सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक विवादों पर विराम लगा दिया है। हाल के दिनों में अनेक उपासना स्थलों से जुड़े मामलों के कोर्ट पहुंचने के बाद से सांप्रदायिक सदभाव को धक्का लगने की आशंका बढ़ गई है। शीर्ष अदालत ने देश को सभी अदालतों को धार्मिक स्थलों, विशेषकर मस्जिदों और दरगाहों पर दबाव करने संबंधी नए मुकदमों पर विचार करने और लंबित मामलों में कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से अगले आदेश तक रोक दिया। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट कहा कि क्योंकि मामला लंबित अदालत में विचाराधीन है, इसलिए पीठ समझती है कि अगले आदेश तक कोई नया मुकदमा दर्ज न किया जाए। उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश से विभिन्न हिंदू पक्षों द्वारा दायर लगभग 18 मुकदमों में कार्यवाही पर रोक लग गई है। इन मुकदमों में बाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही इंदगाह मस्जिद और संभल में शाही जामा मस्जिद समेत 10 मस्जिदों की मूल धार्मिक प्रकृति का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण का अनुरोध किया गया है। वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा वर्ष 2020 में दायर मुख्य याचिका में उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती दी है। कहा गया है कि उपासना स्थल कानून संविधान के धर्मनिरपेक्षता और बराबरी जैसे मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, इस कानून से हिंदुओं को अधिक नुकसान पहुंचता है। इस याचिका का विरोध करते हुए जमियत उलेमा-ए-हिंद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कई एक्टिविस्ट्स ने भी अपनी याचिकाएं दाखिल की थीं। जब देश में अयोध्या विवादित ढांचा को लेकर आंदोलन अपने चरम पर था, तो 18 सितंबर 1991 को केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने उपासना स्थल कानून संसद से पारित कराया था। उपासना स्थल कानून कहता है कि भारत में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था, उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इस कानून के संस्करण 3 में वर्णित है कि इस कानून के तहत, कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल या किसी समुदाय के पूजास्थल के स्वरूप को बदलने की कोशिश नहीं कर सकता। संस्करण 4 (2) में लिखा है कि अगर किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप में बदलाव को लेकर कोई केस, अपील, या अन्य कार्रवाई 15 अगस्त 1947 के बाद किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल, या प्राधिकरण में लंबित है, तो वह केस रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे किसी मामले में दोबारा केस या अपील दायर नहीं की जा सकती। इस कानून में राम जन्मभूमि-बावरी मस्जिद विवाद को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि यह मामला आजादी से पहले ही अदालत में लंबित था। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान मई 2022 में अहम मौखिक टिप्पणी में कहा था कि प्लेसेंस ऑफ वरिंश एक्ट 1991 (उपासना स्थल कानून) 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार, किसी भी संरचना के धार्मिक चरित्र की जांच करने पर रोक नहीं लगाता है। इसके बाद से ऐसे मामलों में अदालतों में बढ़ने लगे। दरअसल, उपासना स्थल विवाद को बढ़ावा देना बर के छत्रों में कंकड़ मारने जैसा है। उपासना स्थल विवाद खत्म होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश पर रोक लगाकर उपासना स्थल विवादों पर फिलहाल विराम लगाने की कोशिश की है। नए आदेश आने तक सभी को उपासना स्थल कानून का सम्मान करना चाहिए।

मुद्दा

बलदेव राज भारतीय



बांग्लादेश संकट : हिन्दू आखिर किसके भरोसे

विश्व के अनेक देशों में आज युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है, वैसा ही एक संकट आज बांग्लादेश में उत्पन्न हो रहा है। इस संकट का बीजारोपण आज नहीं बल्कि अरबों और जिहाद की आड़ में वर्षों पहले ही रोपित हो चुका था। पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार न केवल मानवाधिकारों का हनन है बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता और भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए भी चुनौती बन गया है। बाते कुछ वर्षों में, बांग्लादेश में चरमपंथी ताकतों का उभार हुआ है, और उनके हाथों में सत्ता की चाबी आने के बाद से स्थिति और भी विकट हो गई है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक लंबे समय से उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, पुजारियों पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं, और हिंदू परिवारों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जो लोग धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं होते, उन्हें जान से मार दिया जाता है। इन घटनाओं ने अल्पसंख्यक समुदायों के बीच भय और असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है। ऐसा लगता है कि विश्व मानवाधिकार आयोग वाले कोई सीए पड़े हैं। उन्हें हिन्दू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार दिखाई नहीं पड़ रहे। जिन लोगों को भारत में रहने पर डर लगता था, उन्हें शायद बांग्लादेश की घटनाएं सुकून देने वाली लगती होंगी। हिंदू धर्मस्थलों पर हमलों की घटनाएं बांग्लादेश में चरमपंथी ताकतों की योजनाबद्ध साजिश को उजागर करती हैं। इन घटनाओं का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि सरकारी तंत्र इन पर अंकुश लगाने की बजाय इन्हें बढ़ावा दे रहा है।

मोहम्मद युनुस जैसे नेताओं के प्रभाव के तहत, पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ाई जा रही है। पाकिस्तान से हथियार खरीदे जा रहे हैं और देश में बड़े पैमाने पर सैन्य सामग्री का संग्रह हो रहा है। इस प्रकार के कदम न केवल बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे हैं। हथियारों और सैन्य सामग्री का यह संग्रह स्पष्ट रूप से किसी बड़े उद्देश्य की ओर इशारा करता है। क्या यह भारत के खिलाफ किसी रणनीति का हिस्सा है? क्या बांग्लादेश में उभरते चरमपंथी तत्व क्षेत्र में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे हैं? ये सवाल गंभीर चिंताओं को जन्म देते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। भारत और बांग्लादेश का साझा इतिहास और भूगोल इस संकट के प्रभाव को सीमित करने की अनुमति नहीं देता। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भी लाखों लोग भारत में शरण लेने को मजबूर हुए थे। वर्तमान में भी यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई, तो भारत को एक नए शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश से पलायन कर आए शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक तनाव को बढ़ा सकती है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पहले से ही संसाधनों की कमी है। इन परिस्थितियों में, बड़ी संख्या में शरणार्थियों का आगमन स्थानीय आबादी के साथ संघर्ष का कारण बन सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच लंबी सीमा है, जो कई जगहों पर छिद्रपूर्ण है।

ऐसे में चरमपंथी तत्वों और उनके विचारों का भारत में प्रवेश करना आसान हो सकता है। यह स्थिति भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की शांति और स्थिरता को बाधित कर सकती है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश के साथ सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध बनाए रखने की कोशिश की है। लेकिन अगर बांग्लादेश सरकार चरमपंथी ताकतों पर अंकुश लगाने में विफल रहती है, तो यह द्विपक्षीय संबंधों को कमजोर कर सकता है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति सुधारने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। भारत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बांग्लादेश पर यह दबाव बनाना चाहिए कि वह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवाधिकार संगठनों को इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया तो इसका प्रभाव पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र पर पड़ेगा। भारत सरकार को भी चाहिए कि हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर वह बांग्लादेश को चेतावनी दे और वहां पर हालात सही होने तक समस्त भारत बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ा दे। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि उसकी आंतरिक स्थिरता और विकास तभी संभव है, जब वह सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करे। भारत को भी अपने पड़ोसी देश में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना होगा।

(लेखक इतिहास प्रकटा एवं स्वतंत्र चर्चकार हैं, वे उनके अपने विचार हैं।)



विशेष

विष्णुदेव साय

अंत्योदय' के लक्ष्य के साथ हमारी

सरकार ने अपने पंचवर्षीय कार्यकाल का एक वर्ष पूरा कर लिया। यह सब आपके सहयोग और विश्वास के बूते संभव हो सका। पहले लोकसभा और हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव की हमारी जीत ने इस विश्वास पर मुहर लगाई है कि छत्तीसगढ़ सरकार पर जनता का भरोसा बना हुआ है। गर्व से भरी खुशी यह भी है कि एक राज्य के तौर पर छत्तीसगढ़ ने अपनी स्थापना के 24 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रदेश की जनता जनार्दन का कोटि-कोटि अभिनंदन...! हम सब मिलकर धान का कटोरा कहे जाने वाले अपने राज्य छत्तीसगढ़ को धन-धान्य से परिपूर्ण विकसित राज्य बनाएंगे, यही संकल्प है।

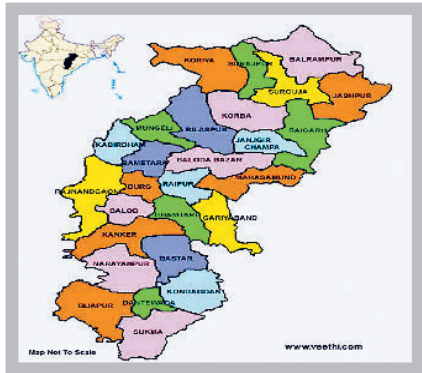
सफल और सार्थक सरकार का एक वर्ष

बीते वर्ष दिसंबर माह में जब मैंने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी तो हमारे समक्ष 'मोदी की गारंटी' को पूरा करने की चुनौती थी। सरकार का खाली खजाना हमें विरासत में मिला था लेकिन कुशल आर्थिक नीतियों और प्रबंधन के बलबूते हमने सभी बड़े वादों को पूरा कर दिखाया है। प्रदेश की आधी आबादी यानि मातृ शक्ति को आर्थिक तौर पर स्ववलंबी बनाने का वादा पूरा करते हुए हमने सर्वप्रथम महतारी वृंदन योजना लागू की। जिसके अंतर्गत 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपए की राशि प्रदान कर राज्य की माताओं-बहनों के सम्मान को बढ़ाया है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ प्रवास पर आईं तो वे इस योजना की लाभार्थी महिलाओं से रूबरू हुईं और कहा कि यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमारे राज्य के अन्नदाताओं को गारंटी दी थी, उस गारंटी को पूरा करते हुए हमने राज्य के 13 लाख किसानों का दो साल का बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रूपए का भुगतान अपनी सरकार के गठन के एक पखवाड़े के भीतर ही कर दी थी। किसान भाईयों के बैंक खाते में बोनस की यह राशि छत्तीसगढ़ के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म-जयंती 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस के अवसर उच्छं हमने सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की थी। प्रधानमंत्री जी की गारंटी के अनुरूप हमने राज्य के किसान भाईयों से प्रति एकड़ 21 किन्टल धान की खरीदी बीते खरीफ सीजन से ही कर रहे हैं। हमने अपने संकल्प को पूरा करते हुए किसान भाईयों को 3100 रूपए प्रति किन्टल के मान से भुगतान भी कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि हम अपने किसानों को धान का सर्वाधिक मूल्य दे रहे हैं। बीते खरीफ सीजन में 145 लाख मेट्रिक टन धान की हमने रिकॉर्ड खरीदी की है। इस साल भी 14 नवंबर से धान की खरीदी जारी है। राज्य में इस साल खरीफ की अच्छी फसल हुई है। धान खरीदी इस साल हम एक और नया रिकॉर्ड बनाएंगे।

राज्य में पूर्ववर्ती सरकार ने अपनी कार्यशैली से 'भरोसे का बहुत बड़ा संकट' पैदा कर दिया था। बीते एक सालों में हमने जनहितैषी कामों से जनता जनार्दन का भरोसा जीता है। जनता में एक नया विश्वास जगा है। विकास का वातावरण निर्मित हुआ है। हमने बनाया था : हम ही संवारेगें' के लक्ष्य के साथ हमारी सरकार जनता-जनार्दन की सेवा में लगी है। राज्य की जनता इतने स्पष्ट थे कि सरकार शासन से सुशासन की ओर चलेगी। हमने युवाओं के सुनहरे भविष्य को राह आसान करते हुए 9000 से अधिक रिक्त पदों पर

सरकारी भर्ती प्रारंभ की है। पीएससी के ताजा परीक्षा परिणामों ने प्रदेश के युवाओं में नए विश्वास और उत्साह का निर्माण किया है। 10 हजार करोड़ की राशि से चार नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं। नगरीय निकायों और पंचायतों में आरक्षण सीमा को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला कर हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चलाने में सभी वर्गों को समान भागीदारी होगी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश को माओवाद-मुक्त बनाने के लिए संकल्पित है। इसी दृष्टि बस्तर क्षेत्र में प्रस्तावित 66 सुरक्षा कैंप में से 42 की स्थापना की जा चुकी है। लाल आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने की



नीति के अनुसार अब तक 213 माओवादियों को मार गिराया गया, 937 नक्सली गिरफ्तार हुए एवं 812 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। माओवाद हिंसा का रास्ता छोड़कर आने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए ठोस नीति बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और छत्तीसगढ़ उसमें पूरे सामर्थ्य के साथ अपना योगदान दे रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 40 लाख घरों तक नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित कर हमने 80 फीसदी लक्ष्य हासिल कर लिया है। पिछले एक वर्ष में इस अभियान ने छत्तीसगढ़ में अपनी रफ्तार पकड़ी है। हर घर को छत देने का वादा पूरा करते हुए हमने अपनी सरकार के गठन के दूसरे ही दिन कैबिनेट को बैठक में 18 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवारों के लिए आवास की स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे 2,044 करोड़ रूपए की पहली किस्त हस्तांतरित की जा चुकी है, ताकि वे अपना घर बना सकें। यह राजनीति का विषय नहीं है लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जनता के साथ छल किया था। इसके उलट एक साल के अंदर हमने सभी वर्गों का विश्वास जीता है। लोगों के चेहरों पर

खुशहाली लाने में कामयाब हुए हैं। अभी तो यह एक पड़ाव मात्र है। जैसा कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास पर उद्घोषित किया था कि विकसित छत्तीसगढ़ तो विकसित भारत, हमारी सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। हम सरगुजा-बस्तर की ओर देखें' की नीति पर काम कर रहे हैं। जनजातियों के कल्याण के लिए हमने आदिवासी गांवों में बुनियादी सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए 'नियद नेल्लानार' योजना शुरू की है। सरकार जल्द ही चना वितरण योजना शुरू करेगी, जिससे 30 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। यह कुपोषण के खिलाफ अमोघ अस्त्र होगा। 148 हाई और हायर सेकेडरी पीएमपी स्कूल में अटल टिकरिंग लैब शुरू करना, आत्मसम्पन्न नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को 15 जगह आवास, पंचदम परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को 147.66 करोड़ की राशि की स्वीकृति, दो हजार मेगावाट की सौर परियोजना, जगदलपुर में 118 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण शुरू करना, सरगुजा-बस्तर के विकास पर विशेष फोकस, नई औद्योगिक विकास नीति का निर्माण, स्वास्थ्य बजट का दुर्गुन होना, ये सारे फैसले हमारे विजन और बुलंद इरादों को दर्शाते हैं।

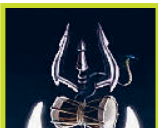
25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी की जयंती है जिसे हम 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाते हैं। अटल जी हमारे राज्य निर्माता हैं। उन्होंने इस भौगोलिक क्षेत्र को नए राज्य के रूप में आकार देकर प्रदेशवासियों की भावनाओं का सम्मान किया। इसी के समानांतर अपने श्रम और प्रतिभा के दम पर छत्तीसगढ़वासियों ने विकास के मामले में खुद को अन्य राज्यों से आगे लाकर खड़ा कर दिया। आंकड़े गवाही दे रहे हैं। राज्य में प्रति व्यक्ति आय 01 लाख 47 हजार 361 रूपए हो गई है, जो तन वर्ष की तुलना में 7.31 प्रतिशत अधिक है। हमने विकास का ज्ञान' मडल अपनाया तथा छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी आने वाले 5 सालों में 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। हमारी नई औद्योगिक विकास नीति का उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा और 2047 के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण की परिकल्पना को साकार करना है। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास हासिल करना, उनके चेहरे पर तस्की और संतोष की मुस्कान दिखें, मेरे मुख्यमंत्री होने की सार्थकता इसी में है।

भारत-रत्न अटलजी की एक कविता की यह पंक्तियां हमें प्रेरित करती हैं कि :
*जीवन को शत-शत आहुति में,
जलना होगा, गलना होगा
कदम मिलाकर चलना होगा।*

-लेखक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं।

हर युग में प्रासंगिक 'महादेव'

कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं आदियोगी शिव का प्रशंसक हूं। प्रशंसक होने का अर्थ है कि उसकी भावनाओं से जुड़ जाना। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं शिव को महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूं, क्योंकि उनका योगदान काल के परे है। इसलिए वे सदा प्रासंगिक हैं। किसी भी पीढ़ी में किसी इंसान की प्रशंसा उस योगदान के लिए की जाती है, जो उसने उस पीढ़ी या आने वाली पीढ़ियों के लिए किया है। इस धरती पर कई ऐसे लोग आए हैं, जिन्होंने दूसरों के जीवन में योगदान



बिना लड़ाई किए धैर्य से भी जीता जा सकता है

महाभारत में युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए राजसूय यज्ञ किया गया था। इसके लिए सभी राजाओं पर जीत हासिल करनी थी। इस काम के लिए अर्जुन ने विजय यात्रा शुरू कर दी। जहां-जहां अर्जुन जा रहे थे, वहां के राजाओं को पराजित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जो राजा अर्जुन की सैन्य स्वीकार कर रहे थे, अर्जुन उन पर कर लगाकर आगे बढ़ रहे थे। इस यात्रा के दौरान अर्जुन कुरु नाम के राज्य में पहुंचे। अर्जुन पहुंचे तो कुरु राज्य के द्वारपाल और लोगों ने अर्जुन से कहा कि आप इस नगर



विश्व के अनेक देशों में आज युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है, वैसा ही एक संकट आज बांग्लादेश में उत्पन्न हो रहा है।

विश्व के अनेक देशों में आज युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है, वैसा ही एक संकट आज बांग्लादेश में उत्पन्न हो रहा है। इस संकट का बीजारोपण आज नहीं बल्कि अरबों और जिहाद की आड़ में वर्षों पहले ही रोपित हो चुका था। पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार न केवल मानवाधिकारों का हनन है बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता और भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए भी चुनौती बन गया है। बाते कुछ वर्षों में, बांग्लादेश में चरमपंथी ताकतों का उभार हुआ है, और उनके हाथों में सत्ता की चाबी आने के बाद से स्थिति और भी विकट हो गई है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक लंबे समय से उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, पुजारियों पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं, और हिंदू परिवारों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जो लोग धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं होते, उन्हें जान से मार दिया जाता है। इन घटनाओं ने अल्पसंख्यक समुदायों के बीच भय और असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है। ऐसा लगता है कि विश्व मानवाधिकार आयोग वाले कोई सीए पड़े हैं। उन्हें हिन्दू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार दिखाई नहीं पड़ रहे। जिन लोगों को भारत में रहने पर डर लगता था, उन्हें शायद बांग्लादेश की घटनाएं सुकून देने वाली लगती होंगी। हिंदू धर्मस्थलों पर हमलों की घटनाएं बांग्लादेश में चरमपंथी ताकतों की योजनाबद्ध साजिश को उजागर करती हैं। इन घटनाओं का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि सरकारी तंत्र इन पर अंकुश लगाने की बजाय इन्हें बढ़ावा दे रहा है।

मोहम्मद युनुस जैसे नेताओं के प्रभाव के तहत, पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ाई जा रही है। पाकिस्तान से हथियार खरीदे जा रहे हैं और देश में बड़े पैमाने पर सैन्य सामग्री का संग्रह हो रहा है। इस प्रकार के कदम न केवल बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे हैं। हथियारों और सैन्य सामग्री का यह संग्रह स्पष्ट रूप से किसी बड़े उद्देश्य की ओर इशारा करता है। क्या यह भारत के खिलाफ किसी रणनीति का हिस्सा है? क्या बांग्लादेश में उभरते चरमपंथी तत्व क्षेत्र में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे हैं? ये सवाल गंभीर चिंताओं को जन्म देते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। भारत और बांग्लादेश का साझा इतिहास और भूगोल इस संकट के प्रभाव को सीमित करने की अनुमति नहीं देता। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भी लाखों लोग भारत में शरण लेने को मजबूर हुए थे। वर्तमान में भी यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई, तो भारत को एक नए शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश से पलायन कर आए शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक तनाव को बढ़ा सकती है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पहले से ही संसाधनों की कमी है। इन परिस्थितियों में, बड़ी संख्या में शरणार्थियों का आगमन स्थानीय आबादी के साथ संघर्ष का कारण बन सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच लंबी सीमा है, जो कई जगहों पर छिद्रपूर्ण है।

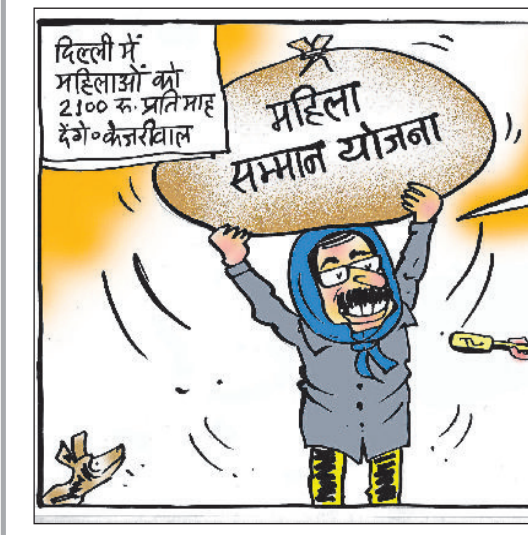
ऐसे में चरमपंथी तत्वों और उनके विचारों का भारत में प्रवेश करना आसान हो सकता है। यह स्थिति भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की शांति और स्थिरता को बाधित कर सकती है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश के साथ सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध बनाए रखने की कोशिश की है। लेकिन अगर बांग्लादेश सरकार चरमपंथी ताकतों पर अंकुश लगाने में विफल रहती है, तो यह द्विपक्षीय संबंधों को कमजोर कर सकता है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति सुधारने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। भारत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बांग्लादेश पर यह दबाव बनाना चाहिए कि वह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवाधिकार संगठनों को इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया तो इसका प्रभाव पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र पर पड़ेगा। भारत सरकार को भी चाहिए कि हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर वह बांग्लादेश को चेतावनी दे और वहां पर हालात सही होने तक समस्त भारत बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ा दे। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि उसकी आंतरिक स्थिरता और विकास तभी संभव है, जब वह सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करे। भारत को भी अपने पड़ोसी देश में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना होगा।

(लेखक इतिहास प्रकटा एवं स्वतंत्र चर्चकार हैं, वे उनके अपने विचार हैं।)

विश्व के अनेक देशों में आज युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है, वैसा ही एक संकट आज बांग्लादेश में उत्पन्न हो रहा है।

विश्व के अनेक देशों में आज युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है, वैसा ही एक संकट आज बांग्लादेश में उत्पन्न हो रहा है। इस संकट का बीजारोपण आज नहीं बल्कि अरबों और जिहाद की आड़ में वर्षों पहले ही रोपित हो चुका था। पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार न केवल मानवाधिकारों का हनन है बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता और भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए भी चुनौती बन गया है। बाते कुछ वर्षों में, बांग्लादेश में चरमपंथी ताकतों का उभार हुआ है, और उनके हाथों में सत्ता की चाबी आने के बाद से स्थिति और भी विकट हो गई है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक लंबे समय से उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, पुजारियों पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं, और हिंदू परिवारों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जो लोग धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं होते, उन्हें जान से मार दिया जाता है। इन घटनाओं ने अल्पसंख्यक समुदायों के बीच भय और असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है। ऐसा लगता है कि विश्व मानवाधिकार आयोग वाले कोई सीए पड़े हैं। उन्हें हिन्दू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार दिखाई नहीं पड़ रहे। जिन लोगों को भारत में रहने पर डर लगता था, उन्हें शायद बांग्लादेश की घटनाएं सुकून देने वाली लगती होंगी। हिंदू धर्मस्थलों पर हमलों की घटनाएं बांग्लादेश में चरमपंथी ताकतों की योजनाबद्ध साजिश को उजागर करती हैं। इन घटनाओं का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि सरकारी तंत्र इन पर अंकुश लगाने की बजाय इन्हें बढ़ावा दे रहा है।

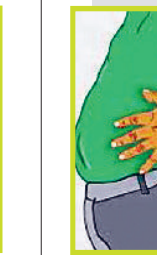
विश्व के अनेक देशों में आज युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है, वैसा ही एक संकट आज बांग्लादेश में उत्पन्न हो रहा है।



करंट अफेयर

हांगकांग में सरकार विरोधी प्रदर्शन के लिए सांसद दोषी

हांगकांग के एक न्यायाधीश ने लोकतंत्र समर्थक एक पूर्व सांसद को जुलाई 2019 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान शहर में एक मेट्रो स्टेशन पर भीड़ द्वारा हिंसा के दौरान दंगा करने के लिए बृहत्पतिवार को दोषी ठहराया। अभियोजकों ने तैम चेउक-टिंग पर लकड़ी के डंडों और धातु की छड़ लिये लगभग 100 लोगों के एक समूह को उकसाने का आरोप लगाया। अभियोजकों के मुताबिक, इन लोगों ने ट्रैन स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों और राहगीरों पर हमला किया। अभियोजकों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने काली शर्ट पहनी थी जबकि कुछ लोगों ने स्फेद शर्ट पहनी हुई थी और वे दावा कर रहे थे कि वे हांगकांग के नये क्षेत्रों के एक आवासीय जिले यूएन लॉन में अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। हिंसा में तैम समेत दर्जनों लोग घायल हो गये थे और इस हिंसा ने विरोध आंदोलन को और तेज कर दिया क्योंकि जनता ने पुलिस की दरी से की गई कार्रवाई की आलोचना की थी। न्यायाधीश स्टैनली वेन ने फैसला सुनाया कि तैम मध्यस्थ के रूप में काम नहीं कर रहा था जैसा कि उसने दावा किया था बल्कि वह राजनीतिक लाभ के लिए स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि तैम के शब्दों ने स्फेद शर्ट पहने लोगों को उकसा दिया।



गलत तरीके से आलसी समझा जाता है और यह माना जाता है कि उनमें इच्छाशक्ति या आत्म-अनुशासन की कमी होती है। बड़े शरीर वाले लोग कार्यस्थल, अंतरंग और पारिवारिक संबंधों, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मीडिया सहित कई क्षेत्रों में भेदभाव का अनुभव करते हैं। वजन को लेकर शर्मिंदगी महसूस करना बढ़े हुए कोर्टिसॉल स्तर (शरीर में मुख्य तनाव हार्मोन), शरीर की नकारात्मक छवि और खराब मानसिक स्वास्थ्य सहित कई नुकसान से जुड़ा हुआ है।

आज की पाती

आज की पाती

आज की पाती

पाक के पास जा रहा बांग्लादेश

1971 के मुक्ति संग्राम के बाद भारत के सैन्य समर्थन से पाकिस्तान से आजाद हुआ बांग्लादेश इन दिनों भारत से दूर और पाकिस्तान के पास जाता नजर आ रहा है। इस साल अग्रस्त में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही वहां सिपायी उथल-पुथल चल रही है और माहौल में भारत के खिलाफ नफरत घोलकर पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाई जा रही है। साफ लगता है कि बांग्लादेश अपने और भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधार रहा है। और संदेश देना चाहता है कि वह अब दक्षिण एशियाई राजनीति को भारत के नजरिए से नहीं देखेगा। हाल के दिनों में पाकिस्तान ने भी ऐलान किया है कि वह बांग्लादेशी नागरिक बिना किसी वीजा शुल्क के उनके देश की यात्रा कर पाएंगे। दोनों देशों में सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने की भी घोषणा की गई है। - संकेत अग्रवाल, भाटापारा

ऑफ बीट

मोटापा लोगों को गहराई तक प्रभावित करता है

ज्यादा वजन वाले लोग एक ऐसे कलंक में जी रहे होते हैं, जो व्यापक है और इन लोगों को कहीं गहराई तक प्रभावित करता है। इसे भेदभाव के अंतिम स्वीकार्य रूपों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। कुछ शोधकर्ता सोचते हैं कि 'मोटापा' शब्द ही समस्या का हिस्सा है, और कलंक को कम करने के लिए नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। उनका सुझाव है कि इसका नाम 'वसा-आधारित पुरानी बीमारी' रख दिया जाए। बड़े शरीर में रहने वाले 42 प्रतिशत वयस्कों को अपने वजन को लेकर शर्मिंदगी का अनुभव होता है। ऐसा तब होता है जब दूसरों की उनके प्रति नकारात्मक भावनाएं, दृष्टिकोण, धारणाएं और निर्णय होते हैं, उन्हें गलत तरीके से आलसी समझा जाता है और यह माना जाता है कि उनमें इच्छाशक्ति या आत्म-अनुशासन की कमी होती है। बड़े शरीर वाले लोग कार्यस्थल, अंतरंग और पारिवारिक संबंधों, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मीडिया सहित कई क्षेत्रों में भेदभाव का अनुभव करते हैं। वजन को लेकर शर्मिंदगी महसूस करना बढ़े हुए कोर्टिसॉल स्तर (शरीर में मुख्य तनाव हार्मोन), शरीर की नकारात्मक छवि और खराब मानसिक स्वास्थ्य सहित कई नुकसान से जुड़ा हुआ है।

टैंड

संविधान का अपमान शर्मनाक

महाराष्ट्र के परभणी मेनारतारन बाबा साहेब ड. गोवार्धन अंबेडकर की प्रतिमा एवं संविधान का किया गया अमानुश अति-निन्दनीय व धर्मनिराक वादों की सरकार, ऐसे जातिवादी व असामाजिक तत्वों के विकृत तुरल सख्त कानूनी कार्रवाई करें। -नायावती, पूर्व सीएम, उग्र

दलितों पर अत्याचार

आज हाथरस जाकर 4 साल पहले हुई शर्मनाक और दुर्गावर्षीय घटना के पीड़ित परिवार से मिले। गुलामाज के देहान उन्वोंने जो बाते बताईं उसने मुझे झकझोर कर रख दिया। इस परिवार की हताया और निराशा माज्जा द्वा़रा दलितों के ऊपर किए जा रहे अत्याचार की सच्चाई को दिखाते हैं। - राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

कानून का शासन लाएंगे

क्रिस्टोफर रे का इस्तीफा अमेरिका के लिए एक महान दिन है क्योंकि वह अन्याय विनाश के रूप में जाने जाने वाले हथियारीकरण को समाप्त कर देगा। अब हम सभी अमेरिकियों के लिए कानून का शासन बहाल करेंगे। -जेनाड टंप, राष्ट्रपति, यूएसए

एआई कार्यक्रम

आशा मय, विद्याल, प्रेम, अनिष्टितता और अक्षर नुस्खी का मिश्रण है। तुझे बंदे है कि कोई भी इन भावनाओं को एआई कार्यक्रम में को

किसान व आम जनता से वादा खिलाफी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर कुसमी में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

कुसमी, 14 दिसंबर। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को एक साल पूरा हो गया है। भाजपा सरकार की नाकामियों को जानता के बिच रखकर कुसमी नगर के बस स्टैंड के समीप में कांग्रेस नेताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन कर जमकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रदेश सरकार पर किसानों व आम जनता से वादा खिलाफी करने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी की गई।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुसमी अध्यक्ष सह जनपद पंचायत

कुसमी के उपाध्यक्ष हरीश मिश्रा ने बताया की भाजपा के एक वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में कानून व्यवस्था सहित विभिन्न जनहित के मुद्दे से आम जनता बर्हाल हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में भाजपा सरकार की एक वर्ष के असफल कार्यकाल में बेहाल हुई छत्तीसगढ़ की स्थिति को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से धरना प्रदर्शन आयोजित किया है।

धरना प्रदर्शन में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आयोजित सभा पर कहा कि



भाजपा के शासनकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बर्हाल है। लगातार प्रदेश में हत्या, लूट, डकैती, चाकू बाजी जैसे कई गंभीर अपराध हो रहे हैं, जिसे रोकने में भाजपा की सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है।

इसके साथ ही समर्थन मूल्य में हो रही धान खरीदी में किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा सरकार ने किसानों को 3100 रुपये देने का घोषणा किया था, लेकिन किसानों को सिर्फ समर्थन मूल्य की राशि

2300 रुपये ही मिल रही है। इसके साथ ही किसानों को टोकन, बारदाना जैसे कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र भगत, जनपद सदस्य देवधान भगत, पूर्व मंत्री अध्यक्ष बालेश्वर राम, पापंद ललित निकुंज, पापंद पति पंकज दुबे, मुजसम अली, सोनू अली, विक्रम गुप्ता, फरीद खान सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

आयोजित सभा में मंच का संचालन युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष दीपक बुनकर ने किया तथा आभार व्यक्त विधानसभा उपाध्यक्ष मुहम्मद

श्राकी ने की।

नपुं चुनाव में कांग्रेस को बहुमत दिलाने जानता से अपील

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हरीश मिश्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र भगत ने आयोजित सभा के बिच जनता से अपील करते हुवे कहा है की आगामी नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है आप सभी कांग्रेस के नीतियों को समझें तथा कांग्रेस को बहुमत देकर विजयी बनायें।

जैसा मैंने यूजिन पटेल को देखा

निर्मल तिग्गा

सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर

28 मार्च 1926 को गाब्रिएल मुंशी और मोनिका के घर पहलौट के रूप में यूजिन तिग्गा का जन्म हुआ और यही आगे चलकर मेरे पिताश्री हुए। दुनिया में कितनी शख्सियत आती हैं और गुमनामी के अंधेरे में विलीन हो जाती हैं। बहुत कम personality ऐसे होते हैं जो unsung hero बन पाते हैं। ऐसी विभूतियां कम होती हैं जिन्हें इतिहास याद रखता है। यूजिन तिग्गा को भी इसी सामान्य श्रेणी में ही गिना जा सकता है। किसी अपने निकटवर्ती जन खासकर पिता के संबंध में कुछ कहना या बताना कम खरेरे का काम नहीं है। इसमें पक्षपात का बड़ा जोखिम है। जो भी हो मैंने

आज यह दुःसाहस तो कर ही दिया है और इसके लिये कलम पर छोड़ दिया है, जो बताना चाहे बताये, जो लिखना चाहे लिखे। सब यश-अपयश उसके सर !

हाँ, तो मैं कह रहा था... उन दिनों गाब्रिएल गिनाबहार मिशन संस्था में मुंशी का काम करते थे अतः उनका परिवार वहीं बसता था। यूजिन की पढ़ाई-लिखाई प्राइमरी से सातवीं मिडिल तक गिनाबहार में हुई। उन्हें हिंदी और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान प्राप्त हुआ। मिडिल पास करने के कुछ समय बाद, एक दिन ऑफिस से लौटकर गाब्रिएल ने पत्नी मोनिका को किशोर यूजिन के बारे में अपना निर्णय सुनाया। सुनकर मोनिका का कोमल मातृहृदय द्रवित हो गया।

महासभा जिला सरगुजा द्वारा कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन ...!

प्रदेश आवाहन पर ओबीसी महासभा के पदाधिकारी ने कलेक्टर से मुलाकात की। कई मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन...

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सरगुजा - ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम साहू के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया जाना तय किया गया था। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष व सरगुजा संभाग के प्रभारी परशुराम सोनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिध मंडल सुभाष साहू प्रदेश सचिव ओबीसी महासभा, आदित्य गुप्ता जिला कार्य समिति सदस्य प्रमुख रूप से



उपस्थित रहे साथ ही सत्यनारायण वर्मा, कृष्णा सोनी, राम अवतार गुप्ता, रघुनंदन, युगल किशोर, विकास ठाकुर, राजेश इनके अलावा ओबीसी महासभा के कई पदाधिकारी एवं सम्माननीय सदस्य गण उपस्थित रहे। ज्ञापन देते हुए ओबीसी महासभा के पदाधिकारी

ने बताया कि अधिकांश संभाग व जिलों में ओबीसी की जनसंख्या 27 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद भी उन्हें जनसंख्या के अनुपात में न देकर अधिकतम 27 प्रतिशत आरक्षण का सीमित प्रावधान किया गया है। जो कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की

हड्डी बहुसंख्यक ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय व असंवैधानिक है। तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल जैसे राज्यों में ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में 50, 49 और 40 प्रतिशत तक आरक्षण लागू है। छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण जो राज्यपाल महोदय के पास लंबित है उसको अभिलंब पास कर पिछड़ा वर्ग के हित में कार्य करने की बात कही गई। अवगत हो कि अधिकांश संभाग, जिलों में ओबीसी की जनसंख्या 27% से अधिक होने के बावजूद भी उन्हें जनसंख्या के अनुपात में न देकर अधिकतम 27% प्रतिनिधित्व का सीमित प्रावधान किया गया है। जो कि प्रदेश के अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी

बहुसंख्यक ओबीसी समुदाय के साथ घोर अन्याय एवं असंवैधानिक है। अवगत हो कि तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल जैसे राज्यों में ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में क्रमशः 50, 49 और 40% प्रतिनिधित्व आरक्षण लागू है। अतः इन राज्यों की भांति 42% प्रतिनिधित्व आरक्षण लागू किए जाने का निवेदन किया गया है। अतः राज्य सरकार को उक्त तथ्यों एवं ऊपर उल्लेखित तीनों राज्यों के आरक्षण व्यवस्था के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आबादी के अनुरूप समानुपातिक प्रतिनिधित्व कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित करने का आग्रह किया गया है।

दोगंभीर रूप से घायल, घायलों का इलाज जारी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

तारा - कोरबा जिले के मोरगा चौकी क्षेत्र अंतर्गत एनएच-130 के पुटा घाट पर मंगलवार सुबह करीब 7 बजे पेट्रोल टैंकर और पिकअप वाहन की आमने-सामने भीषण भिड़ंत में पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में पिकअप सवार पांच अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की स्थिति गंभीर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिकअप वाहन (क्र. यूपी-61बीटी-4748) सासाराम, बिहार से महाराष्ट्र चमल बेचने जा रहा था। वहीं पेट्रोल लोड टैंकर (क्र. सीजी-15एसी-0743) बिलासपुर से अंबिकापुर की ओर



जा रहा था। पुटा घाट पर दोनों वाहनों की जोरदार टक्कर हुई, जिससे पिकअप चालक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना में पिकअप सवार पारस चौहान, सुशीव कुमार राय, अखिलेश चौहान, कमलेश चौधरी और उमापति चौहान घायल हुए हैं। इनमें से दो की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। टैंकर चालक को भी चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही मोरगा

चौकी प्रभारी मंतु राम मरकाम, आरक्षक देवेन्द्र पैकरा, महिपाल सिंह और सरजीत सिंह ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। सभी घायलों को उदयपुर से आई एंबुलेंस द्वारा सीएचसी उदयपुर ले जाया गया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मृतक के परिजनों के आने का इंतजार कर रही है। दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है।

नई औद्योगिक नीति से भारत का इंडस्ट्रियल हब बनेगा छत्तीसगढ़ : विष्णुदेव साय

भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इकोनॉमिक कॉन्फ्लेव में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने साझा किए विचार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से छत्तीसगढ़ को भारत का इंडस्ट्रियल हब बनाने की दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है। इस नीति के तहत क्षेत्रीय आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण एवं औद्योगिक निवेश बढ़ाने पर जोर



दिया गया है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इकोनॉमिक कॉन्फ्लेव में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ऑनलाइन जुड़ कर यह बात कही।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। उन्होंने बताया

कि अगले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ में पांच लाख नौकरियां सृजित की जाएगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन सहित कई अन्य सहायता दी जा रही है, जिसके तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार उपलब्ध कराने पर उद्योगों को उनके वेतन का 40 प्रतिशत तक सॉल्डि के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस नीति के तहत बस्तर में उद्योग लगाने पर स्थानीय पूंजी निवेश अनुदान के तहत उद्योगों को 45% तक की सहायता दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ शासन के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर केन्द्रीय जेल में संगोष्ठी का हुआ आयोजन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर / छत्तीसगढ़ शासन के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर सुशासन का एक साल, छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर में शनिवार को संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक ह्यूएक प्रयास स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर। इस अवसर पर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं आरसेटी अधिकारी अम्बिकापुर श्री श्याम सुन्दर गुप्ता, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से श्री



विरेन्द्र अम्बष्ट, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरसेटी मास्टर ट्रेनर कुमारी तमना निशा उपस्थित रहे। मास्टर ट्रेनर द्वारा जेल में निरूद्ध बंदियों को दिये जाने वाले बैंक ऋण से संबंधित विस्तृत जानकारी

जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, अटल पेंशन योजना, खादी ग्रामोद्योग योजना आदि योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। जेल अधीक्षक

श्री योगेश सिंह क्षत्री द्वारा बताया गया कि इस जानकारी से लाभ प्राप्त कर बंदीगण रिहाई पश्चात अपनी आजीविका व जीविकोपार्जन को प्राप्त करने में सहायक होंगे और अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर समाज में पुनः स्थापित होकर अपनी नैतिक भूमिका निभा सकेंगे। कार्यक्रम में उप जेल अधीक्षक श्री आर. आर. मातलाम, सहायक जेल अधीक्षक श्री ए.के. बाजपेयी, सहायक जेल अधीक्षक श्री संजय कुमार खैरवार सहित समस्त अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

<p>न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)</p> <p>ईशतहार</p> <p>रा०प०क्र०/३१-२/२०२४-२५</p> <p>एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक नेहाल अख्तर पिता अफजल हुसैन जाति मुसलमान निवासी मनेन्द्रगढ़, तहसील मनेन्द्रगढ़ जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम श्रीगढ़ तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 102/7 रकबा 0.010 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की प्रत, आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 29/12/2024 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 13/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।</p> <p>अनुविभागीय अधिकारी (रा), अम्बिकापुर</p>

<p>न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)</p> <p>ईशतहार</p> <p>रा०प०क्र०./अ-२/२०२४-२५</p> <p>एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कमल अख्तर पिता अफजल हुसैन जाति मुसलमान निवासी मनेन्द्रगढ़, तहसील मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम श्रीगढ़, तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 101/4 रकबा 0.010 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की प्रत, आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 29/12/2024 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 13/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।</p> <p>अनुविभागीय अधिकारी (रा), अम्बिकापुर</p>

<p>न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)</p> <p>ईशतहार</p> <p>रा०प०क्र०/अ-२/२०२४-२५</p> <p>एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मो० आरिफ आ० मो० मोईन जाति मुसलमान निवासी नवागढ़ तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम कातिप्रकाशपुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 393/113 रकबा 0.012 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की प्रत, आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 29/12/2024 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 13/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।</p> <p>अनुविभागीय अधिकारी (रा), अम्बिकापुर</p>
--

<p>न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)</p> <p>ईशतहार</p> <p>रा०प०क्र०/अ-२/२०२४-२५</p> <p>एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मुशर्रत खानुम पत्नी मो० ताहिर खान जाति मोहिना निवासी नवागढ़ तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम कातिप्रकाशपुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 393/111 रकबा 0.032 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की प्रत, आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 29/12/2024 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 13/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।</p> <p>अनुविभागीय अधिकारी (रा), अम्बिकापुर</p>
--

<p>न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग०</p> <p>ईशतहार</p> <p>रा०प०क्र०-अ/६/२०२४-२५</p> <p>एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, आवेदक नीलचन्द्र सिंह आ. स्व. रामशंकर सिंह, निवासी गुदरी चौक (डी०सी० रोड) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदक के पिता स्व. रामशंकर सिंह आ. रामलखन सिंह के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अम्बिकापुर, मोहल्ला डी०सी० रोड, स्थित शीट नं. 03 की नजूल भूमि खसरा क्रमांक 1374/3 रकबा 0.12/1/2 एकड़ भूमि है। भू-धारक रामशंकर सिंह की मृत्यु दिनांक 08/04/2021 को हो गई है। उक्त भूखण्ड को पृथक् रामशंकर सिंह द्वारा वसीयतनामा दिनांक 12.03.2020 के माध्यम से आवेदक को प्रदान कर दिया गया है। अतः उक्त वसीयतनामा दिनांक 12.03.2020 के आधार पर आवेदक द्वारा उक्त भूमि के नजूल अभिलेख में स्वयं का नामांतरण कराने हेतु वसीयतनामा दिनांक 12.03.2020 की छायाप्रति, मयदस्तावेज सहित आवेदन पत्र, अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 27/12/2024 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निवृत्त तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 13/12/2024 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।</p> <p>नजूल अधिकारी अम्बिकापुर</p>
--

स्वयंसेवी शिक्षकों को साक्षरता केंद्र संचालन के लिए प्रोत्साहित करें

उल्लास नवभारत साक्षरता की दिलाई गई शपथ

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजनगर - राज्य साक्षरता प्राधिकरण मिशन एवं राज्य साक्षरता केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित कलेक्टर एस जयवर्धन के निर्देशन तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी पंडित भारद्वाज एवं बीपीओ रविनाथ तिवारी के मार्गदर्शन में शासकीय माध्यमिक विद्यालय पतरपाली में संकुल स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था। उक्त बैठक संकुल के समस्त विद्यालय के शिक्षक उपस्थित थे उनके मध्य उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के सफल क्रिया-न्वयन पर चर्चा करते हुए बीपीओ रविनाथ तिवारी ने बताया कि अपने विकासखंड के समस्त ग्राम पंचायत में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप सभी अपने अपने ग्राम पंचायत में नवभारत साक्षरता का प्रचार प्रसार करते हुए साक्षरता केंद्रों में असाक्षरों की सत प्रतिशत उपस्थिति बहाल, उल्लास पुस्तिका का नियमित पाठन, कुजूर सहित संकुल के शिक्षक, शिक्षिकाएं, डिजिटल साक्षरता, विधिक साक्षरता,

शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, स्वच्छता पर जागरूकता के संबंध में नवसाक्षरों को जानकारी देने तथा स्वयं सेवी शिक्षकों को साक्षरता केंद्र संचालन के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिए, वही स्कूल में उपस्थित सभी बच्चों को उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम पंडित भारद्वाज एवं बीपीओ रविनाथ तिवारी के मार्गदर्शन में शासकीय माध्यमिक विद्यालय पतरपाली में संकुल स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था। उक्त बैठक संकुल के समस्त विद्यालय के शिक्षक उपस्थित थे उनके मध्य उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के सफल क्रिया-न्वयन पर चर्चा करते हुए बीपीओ रविनाथ तिवारी ने बताया कि अपने विकासखंड के समस्त ग्राम पंचायत में उल्लास नवभारत

साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप सभी अपने अपने ग्राम पंचायत में नवभारत साक्षरता का प्रचार प्रसार करते हुए साक्षरता केंद्रों में असाक्षरों की सत प्रतिशत उपस्थिति बहाल, उल्लास पुस्तिका का नियमित पाठन, कुजूर सहित संकुल के शिक्षक, शिक्षिकाएं, डिजिटल साक्षरता, विधिक साक्षरता,

डी सिंह, संतोष जायसवाल, योगेश साहू, अनिता सिंह, कृष्णा कुमार यादव, उर्मिला सिंह, प्रवीणा, रघुनाथ जायसवाल, रामधन साहू, नंदकुमार सिंह, धीरेंद्र सिंह, सुखलाल सिंह, सुमेर साय, अजय साहू, अल्का वित्तीय साक्षरता, चुनावी साक्षरता, एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।





सुशासन का साल
छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल

बस्तर ओलंपिक 2024

खेलों के जरिए
सुखद भविष्य
की ओर बढ़ता
बस्तर



श्री अमित शाह
माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



खेलेगा बस्तर
बढ़ेगा बस्तर

हमने बनाया है

हम ही संवारेंगे

हमसे जुड़ने के लिए



Q.R. स्कैन करें

ChhattisgarhCMO
Visit us : DPRChhattisgarh

छत्तीसगढ़
जनसंपर्क
www.dprcg.gov.in

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन के एक वर्ष की उपलब्धियों को मंत्री लक्ष्मी ने किया साझा

0 बोली-सेवा ही सर्वोपरि' छत्तीसगढ़ शासन का मूल मंत्र 0 कलेक्ट्रेट सभागार में हुई मंत्री लक्ष्मी की पत्रकार वार्ता

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन के एक वर्ष का पूरा होने पर शनिवार को यहां जिला कार्यालय में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रेसवार्ता कर सरकार के विभिन्न योजनाओं की सिलसिलेवार उपलब्धियां बताईं। उन्होंने कहा 'सेवा ही सर्वोपरि' छत्तीसगढ़ शासन का मूल मंत्र है जिसका अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने 1 वर्ष पूर्ण कर लिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को साझा किया और बताया कि कैसे एक साल में राज्य ने विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सुशासन की स्थापना के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, पारदर्शिता को बढ़ावा दिया और प्रशासनिक सुधारों के जरिए जनता तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने की दिशा में काम किया। इस अवसर पर पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा, बाबूलाल अग्रवाल, मुरली मोहनर सोनी, शशिनाथ गर्ग, सदीप अग्रवाल, बसन्त कुशवाहा, राजेश्वर तिवारी, अरविन्द मिश्रा, शिव शंकर साहू, कलेक्टर एस जयवर्धन, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश्वर निदिनी साहू व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री ने बताया कि 13 दिसम्बर को हमारी सरकार का

पहला साल पूरा हो गया है। हमारा यह पहला साल आप सभी की सहभागिता और विश्वास के साथ विकास के लिए समर्पित रहा। बीते 12 महीनों में मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में प्रदेश ने विकास के अनेक नये आयाम स्थापित किए हैं। इनमें से कुछ आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। इस एक साल में हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया और उपलब्धियां हासिल की, हमारी प्रार्थना है कि हमारी सरकार ने वे लोग रहे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के नागरिकों से वादा किया था कि सरकार बनने के बाद हम प्रदेश में सुशासन की स्थापना करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करेंगे। सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह तत्परता के साथ कार्रवाई की। जो लोग भ्रष्टाचार के मामलों में लिस पाए जा रहे हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। सुशासन की स्थापना के लिए हम तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सुशासन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारी सरकार ने सुशासन एवं अभिसरण नाम से नया विभाग बनाया है। हमारा प्रयास है कि आम नागरिकों को छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। एक क्लिक में अथवा एक फोन कॉल में उनके काम हो जाने चाहिए। विधानसभा चुनाव के

दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के लोगों को जो गारंटियां दी थी, उनमें से अधिकांश गारंटियों को सरकार ने एक वर्ष की अल्प अवधि में ही पूरा कर दिया है।

पूरी की मोदी की गारंटियां

मंत्री ने बताया कि हमारी सरकार ने किसानों से किया गया वादा पूरा करते हुए 3100

के भीतर ही पूरा कर दिया है। **अंत्योदय के लक्ष्य की ओर** मंत्री ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संदेश के अनुरूप हमारी सरकार ने प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने के लिए लगातार काम किया है। राज्य के जनजातीय समाज के गौरव को फिर से

घाटी के गांव धुड़मारास ने अब विश्व पर्यटन के नक्शे पर जगह बना ली है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इस गांव में पर्यटन के विकास के लिए इसे दुनिया के चुनिंदा 20 गांवों में शामिल किया है। गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के गठन से भी राज्य में पर्यटन के विकास की

रियायत देने का विशेष प्रावधान है। राज्य में एमएसएमई को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए एमएसएमई मंत्रालय बनाने की घोषणा कर दी गई है। नयी उद्योग नीति में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अनिवीर, भूतपूर्व सैनिकों, नक्सल प्रभावित, आत्म-समर्पित नक्सलियों एवं तृतीय लिंग के उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान है।

वादा निभाया

हमने वादा किया था कि हम राज्य में सुशासन स्थापित करेंगे। इसके लिए तकनीक का प्रयोग करते हुए शासन-प्रशासन को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में हमें अच्छी कामयाबी मिली है। भ्रष्टाचार के मामले में हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन के सपने को हम लगातार साकार कर रहे हैं। राज्य में गुड गवर्नेंस स्थापित करने के लिए शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की रियल टाइम मॉनिटरिंग अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। सीएमओ पोर्टल के माध्यम से कोई भी नागरिक शासन की योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और उपलब्धियों की ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकता है। नागरिकरण मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों से सहजता से मुलाकात कर सकें इसके लिए

राज कहा गया है, उसे ही हम सुशासन कहते हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान प्रदेश में नक्सलवाद का तेजी से उन्मूलन किया गया है। सरकार ने दो साल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया करने का संकल्प लिया है। बीते एक वर्ष में 213 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। करीब 1750 नक्सलियों को या तो आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया गया है, या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी एक बड़ी कामयाबी यह भी है कि हम नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से बस्तर के अंदरूनी गांव तक लोकतंत्र और विकास की किरणों को पहुंचाने में सफल हुए। हमने नक्सल क्षेत्रों में बंद पड़े स्कूलों को फिर से शुरू कराया है। बस्तर में बस्तर ओलंपिक का आयोजन करके हमने वहां के युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा है। माओवादी आतंक पीड़ित जिलों के विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण तथा शेष जिलों के विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने का निर्णय लिया गया है।

शिक्षा की नयी अलख जगाई

राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करके शिक्षा को रोजगार परक बनाया है। राज्य की प्रतिभाओं को निखारने के लिए रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश की 13 नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरियों के

रहा है। इससे नवा रायपुर और भी तेजी से विकसित होगा। सिम्स बिलासपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से भवन विस्तार का कार्य किया गया है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया। जांजगीर-छांवा, कबीरधाम, मनेन्द्रगढ़ और गौदम मेडिकल कॉलेजों की निर्माण के लिए 1020 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। **केंद्र का साथ, सहयोग और मार्गदर्शन बनी ताकत**

प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने से एक साल में राज्य ने बहुत तेजी से प्रगति की है। केन्द्र से हमें भरपूर सहयोग और समर्थन मिला है। इस दौरान 31 हजार करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत की गई हैं। दो सालों में छत्तीसगढ़ में सड़कों का मजबूत नेटवर्क होगा। साथ ही रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए हमें केन्द्र से अनेक महत्वपूर्ण रेल लाइनों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। हमने इस खास वर्ष में खास उपलब्धियां हासिल करने के लिए खास तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1 नवंबर 2025 को जब हम प्रदेश स्थापना की रजत जयंती मनाएंगे तब 2028 तक प्रदेश की जीएसडीपी को दस लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। हमारे विकास और विश्वास को इस यात्रा में आप हमेशा साक्षी और सहभागी रहे हैं। शासन के विकास कार्यों और लोक हितकारी योजनाओं को जनता



रुपए प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की रिकॉर्ड खरीदी की। हमारी सरकार ने अपने वादे के मुताबिक किसान भाई-बहनों को दो साल के बकाया धान बोनास की राशि 3716 करोड़ रुपए का अंतरण भी किया। प्रदेश की माताओं-बहनों से किए गए वादे को पूरा करते हुए तीन माह के भीतर ही महतारी वंदन योजना शुरू की गई। इसका लाभ 70 लाख माताओं-बहनों को मिल रहा है। अब तक इस योजना की 10 किरतों में 6530 करोड़ रुपए अंतरित किए जा चुके हैं। जरूरतमंद परिवारों के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के अपने वादे को पूरा करने के लिए सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। इस

ऊंचाई पर स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। उनकी आय और रोजगार में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए गए। तेरहवां संग्रहण दर 4 हजार रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5.5 हजार मानक बोरा कर दी गई। जनजातीय क्षेत्रों में सड़क व अन्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अम्बिकापुर के हवाई अड्डे से भी अब हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के विकास के लिए गठित प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व को और मजबूत किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन भी किया गया है।

जनजातीय समाज का बड़ा गौरव

जनजातीय गौरव दिवस के

संभावनाओं को बल मिला है। राज्य में पांच शक्तिपीठों का विकास किया जा रहा है। इसके लिए चार धाम की तर्ज पर एक हजार किलोमीटर की परियोजना शुरू की जा रही है। छत्तीसगढ़ के साथ भगवान राम का गहरा नाता है। वे हमारे भांजे हैं। उन्होंने वनवास के 14 सालों में से 10 साल यहीं गुजारे। हमारी सरकार की कोशिश है कि दुनिया भगवान श्रीराम से हमारे इस रिश्ते को जानें। प्रदेश में श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करके हमने यहां के श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की, ताकि भगवान राम से अपने रिश्ते को और स्पष्ट कर सकें। हम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी शुरू कर रहे हैं। हमने राजिम कुंभ कल्प का वैभव फिर से लौटाया है।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, पीटीएस, मैनापाट, जिला सरगुजा (छ.ग.) हाऊसकीपिंग (साफ-सफाई) कार्य हेतु निविदा/भावपत्र आमंत्रण सूचना

(निविदा दिनांक 01.01.2026 से 31.12.2025 तक के लिए)

निविदा विज्ञापित क्र. : पुअ / पीटीएस/ मैनापाट/ फड/ 03 / 2024 दिनांक 10 12.2024

पीटीएस मैनापाट, जिला सरगुजा के प्रशासनिक भवन, गेस्ट हाऊस, एनजीओ होस्टल बैक, नव आरक्षक बैक, डायनिंग हॉल, पुष्प टॉयलेट-बाथरूम और परिसर अंदर की हाऊसकीपिंग (साफ-सफाई) कार्य हेतु वार्षिक अनुबंध पर ठेका दिये जाने हेतु दिनांक 24.12.2024 के 15:00 बजे अपराह्न तक सीलबंद लिफाफे/भावपत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ऐसी इच्छुक संस्था/फर्म जिन्हें किसी शासकीय/ अर्धशासकीय/निगमित निकायों/ सार्वजनिक उपक्रमों में कार्य करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो वे निर्धारित निविदा प्रपत्र, नियम एवं शर्तें इस कार्यालय से प्राप्त कर, निर्धारित धरोहर राशि के साथ आवेदन कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र आवेदन पत्र के साथ रुपये 500.00 (पांच सौ मात्र) का चालान कोषालय में लेखा शीर्ष 0055 पुलिस शीर्ष 800 अन्य प्राथमिक मद में जमा कर चालान की मूल प्रति पीटीएस मैनापाट कार्यालय में प्रस्तुत कर दिनांक 20.12.2024 के 15:00 बजे तक कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

01. निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि - 20.12.2024 के 15:00 बजे तक।
02. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि - 24.12.2024 के 15:00 बजे तक।
03. निविदा खोलने की तिथि - 26.12.2024 के 12:30 बजे।
(नोट :- निविदा प्रपत्र विक्रय स्थल- पीटीएस मैनापाट, जिला सरगुजा (छ.ग.))

पुलिस अधीक्षक
पीटीएस, मैनापाट
जिला सरगुजा

जी-242504509/5

निर्णय पर तेजी से अमल करते हुए आवासों के निर्माण के लिए बड़ी राशि भी जारी की गई। हमारी सरकार ने प्रदेश के 68 लाख गरीब परिवारों को पांच साल तक मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की। लोकतंत्र सेना नियंत्रण की पेंशन बहाल करने के साथ-साथ पांच साल के एरियर्स का भुगतान भी किया। इस तरह हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अधिकांश गारंटियों को एक साल

अवसर पर राज्य के बैगा, गुनियार, सिरहा को सालाना पांच-पांच हजार रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। जनजातीय गांवों में अखरा निर्माण विकास योजना शुरू की गई है। जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा नायकों की स्थान-स्थान पर प्रतिमाएं लगाने का निर्णय भी लिया गया है। बस्तर में पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यह बड़ी उपलब्धि है कि कोरगे

नई उद्योग नीति से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास की नई संभावनाओं का सृजन हुआ है। यह नीति प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। हमने इस नीति को रोजगार परक बनाया है। नई उद्योग नीति में युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसमें पर्यटन को भी उद्योग के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को भी

मंत्रालय में प्रवेश के लिए स्वागतम पोर्टल और घर बैठे रजिस्ट्री के लिए सुगम एप शुरू किया गया है। राज्य के कार्यालयों में कामकाज में तेजी और सटीकता लाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली शुरू की गई है। खनिजों के ऑनलाइन ट्रांजिट पास की व्यवस्था की गई है। जेम पोर्टल के माध्यम से शासकीय खरीदी और सेवाएं प्राप्त करने को अनिवार्य किया गया है। पुराणों में जिसे राम-

निर्माण का निर्णय लिया गया है। अपने वादे के मुताबिक हमने सीजीपीएससी परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया है। पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हुईं और उनके परिणाम घोषित हुए। इससे राज्य की प्रतिभाओं का विश्वास सीजी पीएससी पर लौट आया है। नवा रायपुर को हम आईटी हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमी कॉरिडोर का निर्माण तेजी से हो

के बीच में ले जाने आप सबका सहयोग महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर मैं आप सबको भी धन्यवाद देती हूँ। प्रदेश की जनता का उनके समर्थन और विश्वास के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। हम सभी छत्तीसगढ़ को विकसित बना कर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में अपना अमूल्य योगदान देंगे।

जनसंपर्क विभाग द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। यहां जिला संयुक्त कार्यालय प्रांगण में सुशासन का एक साल, छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल पर आधारित जिले के विकासमूलक फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन जिले के नागरिकों द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन के एक वर्ष पूरा होने पर जिला कार्यालय परिसर में 'सुशासन का एक साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल' के

थीम में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को

प्रदर्शनी लगाई गई है। फोटो प्रदर्शनी का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाना है। इसमें विभिन्न शासकीय योजनाओं की लाभ और उनके क्रियान्वयन की तस्वीरों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। इसका साथ ही जिला कार्यालय में आने वाले नागरिकों को योजनाओं से संबंधित पत्रिकाओं

जनसामान्य तक पहुंचाने और जन मन का वितरण भी किया गया।



उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम पर पतरापाली स्कूल में दिलाई गई शपथ

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। राज्य साक्षरता प्राधिकरण मिशन एवं राज्य साक्षरता केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित कलेक्टर एस. जयवर्धन के निदेशन तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी पंडित भारद्वाज एवं बीपीओ रविनाथ तिवारी के मार्गदर्शन में शासकीय माध्यमिक विद्यालय पतरापाली में संकुल स्तरीय बैठक का

आयोजन किया गया था। उक्त बैठक संकुल के समस्त विद्यालय के शिक्षक उपस्थित

थे, उनके मध्य उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए बीपीओ रविनाथ तिवारी ने

बताया कि अपने विकासखंड के समस्त ग्राम पंचायत में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप सभी अपने अपने ग्राम पंचायत में नवभारत साक्षरता का प्रचार प्रसार करते हुए साक्षरता केंद्रों में असाक्षरों की शत प्रतिशत उपस्थिति बढ़ाएं, उल्लास क्रियान्वयन का नियमित पाठन वित्तीय साक्षरता, चुनावी साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, विधिक साक्षरता, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, स्वच्छता पर जागरूकता के संबंध में नवसाक्षरों को जानकारी देने तथा स्वयं सेवीशिक्षकों को साक्षरता केंद्र संचालन के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिए। वहीं स्कूल में उपस्थित सभी बच्चों को उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम का शपथ दिलाया गया। इस दौरान संकुल प्राचार्य हेमसाय सिंह, संकुल समन्वयक जी.डी. सिंह, संतोष जायसवाल, योगेश साहू, अनिता सिंह, कृष्ण कुमार यादव, उर्मिला सिंह, प्रवीणा, रघुनाथ जायसवाल, रामधन साहू, नंदकुमार सिंह, धीरेंद्र सिंह, सुखलाल सिंह, सुरेश साय, अजय साहू, अलका कुजूर सहित संकुल के शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।



छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग
कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.1,
अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
eProcurement Portal: <https://eproc-cgstate.gov-in>
(प्रथम आमंत्रण)
निविदा सूचना क्रमांक : 05 / व.ले.लि / 2024-25, दिनांक 06.12.2024 निम्नालिखित कार्यों के लिये दिनांक 27.12.2024 (17.30 बजे) तक ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :-

श्रुप क्र.	सिस्टम निविदा क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत
1	162361	बटवाही करीलकोवा नाला में एनीकट सह पुलिसिया निर्माण कार्य।	₹. 245.94 लाख।
2	162362	लमगांव स्टापडेम कम काजवे निर्माण कार्य।	₹. 246.94 लाख।
3	162363	कोराकछार एनीकट योजना का निर्माण कार्य।	₹. 247.84 लाख।
4	162366	रजपुरी स्टापडेम योजना का निर्माण कार्य।	₹. 251.17 लाख।
5	162367	पैगा स्टापडेम योजना का निर्माण कार्य।	₹. 253.53 लाख।
6	162368	बमलाया झीगा नाला एनीकट योजना का निर्माण कार्य।	₹. 281.55 लाख।

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्वोरमेंट वेब साइट <https://eproc.cgstate.gov.in> पर दिनांक 13.12.2024, समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड किये जा सकते हैं।
नोट : निविदा में माग लेने हेतु टेकेंदारों को ई-प्रोक्वोरमेंट वेबसाइट <https://eproc.cgstate.gov.in> पर नामांकित/पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत टेकेंदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग क्र. 1,
अम्बिकापुर (छ.ग.)
कृते - मुख्य अभियंता
हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

जी-242504563 / 1

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड- बलरामपुर (छ.ग.)
E-mail: echalram-phe-cg@nic.in

रुकी की अभिव्यक्ति क्र. /03/ले.शा/ज.जी.मि/का.अ./लो.स्वा.यां.वि./2024 बलरामपुर, दिनांक 11.12.2024

ऑनलाइन द्वितीय निविदा आमंत्रण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से जल जीवन मिशन अंतर्गत आईएसए. के लिए निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है -

सि. नि. क्र.	आईएसए. का कार्य (रु.करोड़ में)
162754	2.46

निविदा एवं कार्य का विस्तृत विवरण यथा धरोहर राशि, बिड वैधता की तिथि, कार्य की अवधि, निविदाकार की श्रेणी, एवं कार्य तथा स्थल संबंधी जानकारी ऑन लाईन ई-प्रोक्वोरमेंट <https://eproc.cgstate.gov.in> पर दिनांक 17.12.2024 से देखी जा सकती है तथा निविदा दिनांक 07.01.2024 तक बिड डाली जा सकती है। निविदा में आगामी संशोधन पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किए जायेंगे। अतः निविदाकार ऑन लाईन निविदा प्रक्रिया में सतत संपर्क में रहें। अन्य विवरण कार्यालयीन समय पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड बलरामपुर में देखे जा सकते हैं।

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खण्ड-बलरामपुर (छ.ग.)

जी-242504543 / 10

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड- बलरामपुर (छ.ग.)
E-mail: echalram-phe-cg@nic.in

रुकी की अभिव्यक्ति क्र. /04/ले.शा/ज.जी.मि/का.अ./लो.स्वा.यां.वि./2024 बलरामपुर, दिनांक 12.12.2024

ऑनलाइन निविदा आमंत्रण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से जल जीवन मिशन अंतर्गत Kala Jutha/Kala Mandli/ Nacha dal के विभिन्न कार्यों के लिए रुकी की अभिव्यक्ति हेतु निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है -

सि. नि. क्र.	कार्य की अनुमानित लागत (रु.लाख में)
162793	31.48

निविदा एवं कार्य का विस्तृत विवरण यथा धरोहर राशि, बिड वैधता की तिथि, कार्य की अवधि, निविदाकार की श्रेणी, एवं कार्य तथा स्थल संबंधी जानकारी ऑन लाईन ई-प्रोक्वोरमेंट <https://eproc.cgstate.gov.in> पर दिनांक 19.12.2024 से देखी जा सकती है तथा निविदा दिनांक 08.01.2024 तक बिड डाली जा सकती है। निविदा में आगामी संशोधन पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किए जायेंगे। अतः निविदाकार ऑन लाईन निविदा प्रक्रिया में सतत संपर्क में रहें। अन्य विवरण कार्यालयीन समय पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड बलरामपुर में देखे जा सकते हैं।

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खण्ड-बलरामपुर (छ.ग.)

जी-242504566 / 2

सरगुजा फ्रंटलाइन

संपर्क करें

समाचार, ईशतहार, विज्ञापन
हेतु संपर्क करें।दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन
गौरव पथ, गुरुद्वारा के पास बाबूपारा
अम्बिकापुरमो. 9713108088
8719000259

अडाणी पर मेहरबान अधिकारियों ने घाटबरा के ग्रामीणों का बढ़ाया आक्रोश

परिसंपत्तियों के विवरण में गंभीर खामियां, ग्रामीणों ने संपत्ति का परीक्षण करने गांव में आकर करने कहा

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोल परियोजना हेतु न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, उदयपुर, सरगुजा (छ.ग.) द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 21 (1) के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु ग्राम घाटबरा के प्रकरणों के लिए सूचना-पत्र का प्रकाशन कर 3 दिनों, 11 से 13 दिसंबर तक दावा आपत्ति का सुनवाई किया गया। सूचना प्रकाशित करके प्रभावितों को सूचित किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी उदयपुर के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर निम्नलिखित भूमि पर अपने स्वत्व, अर्जित क्षेत्रफल, किस्म भूमि, निहित अंश अथवा क्षतिपूर्ति के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो लिखित में दस्तावेजी प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करें। साथ ही



अनुपस्थित रहने की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई करके नियमानुसार मुआवजा निर्धारित करने की बात कही गई। भूमि का विवरण, क्षेत्रफल एवं परिसंपत्ति के विवरण की जानकारी का सूचना प्रकाशित होने के बाद ग्राम घाटबरा के ग्रामीणों में आक्रोश पनप गया। ग्रामीणों ने 11 दिसंबर को अनुभागी कार्यालय पहुंचकर एसडीएम बन सिंह नेताम से मिलकर अपनी परेशानियों से अवगत कराया तथा ग्राम में ही अधिकारी-कर्मचारियों को भेज कर संपत्ति का परीक्षण करने की

बात कही, जिस पर एसडीएम ने ग्रामीणों की बात को मानकर 12 एवं 13 दिसंबर को ग्राम घाटबरा में ही दावा आपत्ति का आवेदन लिया। चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि परिसंपत्तियों के विवरण का प्रकाशन में बहुत ज्यादा खामियां हैं। प्रकाशन किए गए सूची में किसी का घर तो किसी का मवेशी छूटा, किसी ने पेड़ों की जानकारी गलत भरने या परिसंपत्ति में उसे शामिल नहीं करने का आरोप लगाया। यहां तक कि ग्राम के सरपंच का परिसंपत्ति का विवरण ही गलत

दर्ज था, जिस पर उन्होंने एसडीएम से इनमें सुधार करने की मांग की। ग्राम के अन्य लोगों ने जिस तरह की समस्याएं बताईं उनमें भूमि के कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि वर्तमान स्थिति में भूमि पर काबिज कोई और है और मुआवजा प्रकरण किसी और के नाम पर दिख रहा है। कई ऐसे प्रकरण भी सामने आए जिनमें भूमि की रजिस्ट्री के पेपर तो भूमि स्वामियों के पास हैं परंतु उनके वर्तमान बी वन खसरा में पूर्व के जमीन मालिक या किसी अन्य के नाम दर्ज रहे हैं।

परिवारिक बंटवारा के तहत जिन परिवारों में चार लोग हैं चारों के मकान अलग हैं परंतु उनमें सिर्फ एक या दो के ही मकान का विवरण प्रदर्शित हो रहा है, इस पर भी लोगों ने आपत्तियां दर्ज की हैं। 100 से अधिक ऐसे प्रकरण हैं, जिनमें इस तरह की परेशानियां आई हैं और लोगों ने अपनी आपत्तियां दर्ज करा सुधार की मांग की है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि अभी तक उन्हें इस बात का पता ही नहीं है क्यों उन्हें विस्थापन कहा गया है, किस गांव में उन्हें विस्थापित करके भेजा जाएगा।

ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। तीन दिनों में यदि पूरे आवेदन जमा नहीं हो पाए तो ग्रामीणों को कुछ और वक्त दिया जाएगा। शासन के नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
बन सिंह नेताम
अनुविभागीय अधिकारी

विधायक दे रहे थे सुशासन की दुहाई, इधर भाजपा नेता भड़के



छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। कलेक्टरेट के सभागार में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा विधायक भैयालाल राजवाड़े ने सरकार के एक साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सुशासन का एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा किया है। इधर सुशासन को लेकर चल रहे खचान के बीच भाजपा के जिला उपाध्यक्ष ने भड़कते हुए प्रधानमंत्री आवास निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते बहुत कुछ कह डाला।

पत्रकारों से चर्चा के दौरान विधायक भैयालाल राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश की पहली सरकार है जिसने अपने कार्यकाल के पहले ही साल में जनता से किए गए वादों को समय पर पूरा किया है। उन्होंने कहा सरकार की योजनाएं और नीतियां समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं लाई गई हैं, जिनसे उन्हें सीधा लाभ मिला है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को रिपोर्ट कार्ड के रूप में पेश किया और कहा कि इस रिपोर्ट कार्ड में सरकार की प्राथमिकताओं और

कलेक्टरेट के सभागार में सरकार के एक वर्षीय कार्यकाल के रिपोर्ट कार्ड को पत्रकारों से चर्चा
उन पर हुई प्रगति को दिखाया गया है। पिछले एक साल में विकास के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए गए हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे का विकास, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, और शिक्षा क्षेत्र में नई योजनाओं का शुभारंभ शामिल है। विधायक ने केंद्र की मोदी सरकार की सराहना की, उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से प्रदेश को नई दिशा और दशा

मिली है। विष्णु देव साय के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। भविष्य में कई नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिसको आम लोगों को लाभ मिलेगा। इस दौरान ओम प्रकाश सोनी, दिलीप सोनी, बिहारी पाल, गोपाल कृष्ण मिश्रा के अलावा वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
भ्रष्टाचार के आरोपों पर गरमाया माहौल
प्रेस वार्ता के बीच में माहौल उस समय गरमा गया जब भाजपा जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी ने प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। भैयालाल राजवाड़े सरकार के सुशासन और विकास कार्यों की दुहाई देने में लगे थे, इधर की प्रगति की जानकारी दे रहे थे, तभी ओम प्रकाश ने कहा कि वे बलरामपुर जिला मुख्यालय के भनौरा गांव का निरीक्षण करें, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी अनियमितताएं हुई हैं। कांग्रेस सरकार के दौरान 61 मकानों को पूरा बताया गया, लेकिन इनमें से 34-35 मकानों का भी निर्माण नहीं हुआ है। कई मकान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। आवास बने ही नहीं और पैसा हड़प लिया गया। इस मामले को जिला पंचायत, जनपद पंचायत, बलरामपुर कलेक्टर, स्थानीय विधायक, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल तक पहुंचाने के बाद भी दौड़ियों पर कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। हालांकि, भाजपा नेता मामला अखबार की सुखियां न बने, इसका प्रयास करते अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में जांच हुई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

उप स्वास्थ्यकेंद्र लक्ष्मणगढ़ बंद, मरीज हो रहे परेशान

छ.ग.फ्रंटलाइन उदयपुर। सरगुजा जिले के उदयपुर मुख्यालय के ग्राम लक्ष्मणगढ़ स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र हमेशा बंद रहता है, जिससे आसपास के गांव के मरीजों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्र सेक्टर लक्ष्मणगढ़ के आसपास के ग्राम मानपुर, महेशपुर, फुनगु, सानीबरी, सुखरीभंडार, सेमीधोधा, तेंदुटिकरा के लोगों ने बताया कि गांव के मरीज जब भी स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मणगढ़ पहुंचते हैं तो वहां ताला जड़ा रहता है, जिससे उन्हें 10 किलोमीटर की दूरी अलग से तय करनी पड़ती है। मरीजों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि यह रवैया एक वर्ष से लगातार चल रहा है। महीने में दो-चार दिन ही उप स्वास्थ्य केंद्र खुलता है, बाकी समय हमेशा ताला बंद रहता है। एक वर्ष पहले भी अस्पताल बंद पाए जाने पर ग्रामीणों ने स्वास्थ्य



कर्मियों पर नदारत रहने का आरोप लगाया था। कहना है कि उदयपुर स्वास्थ्य विभाग व बीएमओ की मिलीभगत से पिछले बार जांच में कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक महीने ड्यूटी के प्रति तटस्थता दिखाने के बाद फिर से स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल में ताला बंद करके गांव रहने लगे हैं।
मरीज नीमहकीम या निजी चिकित्सक के यहां जाने विवश
शनिवार को ग्राम लक्ष्मणगढ़ के राजेंद्र प्रसाद बिड़िया लगभग 2

बच्चे बच्चे और बीमार पत्नी को लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मणगढ़ पहुंचे तो अस्पताल में ताला बंद मिला। जिम्मेदारों को फोन भी नहीं लगा, जिससे उन्हें निराशा होकर 10 किलोमीटर दूर सीएससी उदयपुर जाना पड़ा। आगरसाय भी उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला बंद मिलने पर निराशा होकर घर वापस लौट गया और नीमहकीम से इलाज कराया। सोनेलाल अपनी बुजुर्ग मां का तबियत खराब होने पर उप स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मणगढ़ पहुंचा,

तो स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा था। अस्पताल के कर्मचारियों से फोन पर संपर्क नहीं हुआ। बाद में वह उदयपुर से प्राइवेट डॉक्टर को बुलवाकर अपनी मां का इलाज कराया। अस्पताल में आरती सिंह, गोमती सिंह व अनिता राजवाड़े कर्मचारी हैं, जिसमें से एक को हमेशा अस्पताल में रहना है लेकिन अस्पताल बंद मिलता है, जबकि दीवार में खुलने का समय सारणी 10.30 से 5.30 तक उल्लेखित है।
गैर जिम्मेदारों को हटाया जाए-शिवभजन
ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ़ के सचिव शिव भजन सिंह से बात करने पर वह बताया कई बार अस्पताल बंद रहने का शिकायत आ चुका है। आज भी सुबह से अस्पताल बंद है। ड्यूटी नहीं करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और दूसरे कर्मचारियों की पदस्थापना होनी चाहिए।

वाडों का आरक्षण 19 दिसंबर को

छ.ग.फ्रंटलाइन जरही/भटगांव। सूरजपुर के नगरीय निकायों नगर पालिका परिषद सूरजपुर, नगर पंचायत जरही, नगर पंचायत भटगांव, नगर पंचायत विश्रामपुर, नगर पंचायत प्रतापपुर के वाडों का आरक्षण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वाडों का आरक्षण 1994 के प्रावधानों के तहत 19 दिसंबर को जिला कार्यालय सभाकक्ष में संपन्न कराया जाना है, जिसका समय नगर पालिका परिषद सूरजपुर का 12.30 से 1.30 बजे तक, नगर पंचायत जरही का 1.30 से 2.30 बजे तक, नगर पंचायत भटगांव का 2.30 से 3.30 बजे तक, नगर पंचायत विश्रामपुर का 3.30 से 4.30 बजे तक, नगर पंचायत प्रतापपुर का 4.30 से 5.30 बजे तक निर्धारित है। जिले के सभी राजनीतिक दल के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों से उक्त तिथि को निर्धारित समय में उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा है।

पत्नी के हत्या के मामले में आरोपी पति गिरफ्तार

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। हत्या के मामले में बतौली थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके घटना में प्रयुक्त लकड़ी का फारी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक 8 दिसम्बर को रात करीब 8 बजे सनमुनी नामक महिला के साथ घर के बाहर पति ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें उसे सिर में अन्दरूनी चोट आई थी। ईलाज दौरान सीतापुर अस्पताल में वह दम तोड़ दी थी। सीतापुर थाना पुलिस ने मार्ग कायम कर मामले की विवेचना कर रही थी। घटनास्थल जांच दौरान पुलिस ने पाया कि 08 दिसम्बर की रात को पहल राम अपनी पत्नी मृतिका सनमुनी से शराब पीने के लिए पैसा मांगा, लेकिन वह इंकार कर दी। रुपये नहीं देने के कारण आरोपी पति ने अपनी पत्नी सनमुनी के साथ मार पीट की घटना को अंजाम दिया था और उसके सिर को दिवार से टकरा दिया। इसके बाद लकड़ी के फारी से चेहरा एवं कंधा में चोट पहुंचाया था, 10 दिसम्बर को सीतापुर अस्पताल में महिला की मौत हो गई। मामले में प्रार्थी राम कोरवा की रिपोर्ट



पर थाना बतौली में धारा 103(1) चीपएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी पहल राम पिता स्व. बंधन राम 40 वर्ष निवासी बिरौमकेला पटेलपारा को गिरफ्तार करके पुलिस पृच्छाछ की और लकड़ी के फारी को जप्त किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक अशोक शर्मा, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह, आरक्षक राजेश खलखो, मुरलीधर यादव, देवनाथ भगत, नवीन खलखो, भगुल राम रौंकरा एवं महिला आरक्षक मेरी क्लारेट तिकी शामिल रहे।

कीटनाशक का सेवन किए युवक की मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। बलरामपुर जिला के सनावल थाना अंतर्गत ग्राम इंद्रवतीपुर निवासी शत्रुघन पिता रामबितल खैरवार 20 वर्ष की कीटनाशक का सेवन करने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया मृतक 12 दिसम्बर को रात को शराब का सेवन करने के बाद कीटनाशक का अज्ञात कारणों से सेवन कर लिया था। स्वजन उसे सनावल स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, यहां से रेफर करने पर बलरामपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। 13 दिसम्बर को यहां से भी चिकित्सकों ने आवश्यक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया था। मेडिकल कॉलेज अस्पताल अम्बिकापुर में उपचार के दौरान शुकवार की शाम को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया है।

ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय को लेकर सरकार का कराया ध्यानाकर्षण

प्रदेश आह्वान पर ओबीसी महासभा ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम साहू के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ शासन, उपमुख्यमंत्री अरुण साव व नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के नाम ज्ञापन सौंपा। इसी क्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष व सरगुजा संभाग के प्रभारी परशु राम सोनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधमंडल सुभाष साहू, प्रदेश सचिव ओबीसी महासभा, आदित्य गुप्ता जिला कार्य समिति सदस्य के अलावा सत्यनारायण वर्मा, कृष्णा सोनी, राम अवतार गुप्ता, रघुनंदन, युगल किशोर, विकास ठाकुर, राजेश सहित ओबीसी महासभा के कई पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि अधिकांश संभाग व जिलों में



ओबीसी की जनसंख्या 27 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद उन्हें जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण न देकर अधिकांश 27 प्रतिशत आरक्षण का सीमित प्रावधान किया गया है, जो बहुसंख्यक ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय व असंवैधानिक है। तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल जैसे राज्यों में ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में 50, 49 और 40 प्रतिशत तक आरक्षण दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 27 प्रतिशत आरक्षण राज्यपाल के पास लंबित है, उसको अंतिम रूप देकर पिछड़ा वर्ग के हित में कार्य

किया जाना चाहिए। राज्य सरकार से उक्त तथ्यों एवं उल्लेखित तीनों राज्यों के आरक्षण व्यवस्था के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आबादी के अनुरूप समानुपातिक प्रतिनिधित्व करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करने का आग्रह किया गया है। ओबीसी महासभा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ओबीसी समाज के हित में अगर विधेयक पारित नहीं होने पर ओबीसी महासभा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी।

होली क्रॉस वीमेन्स कॉलेज में एनुअल स्पोर्ट्स मीट संपन्न

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। होली क्रॉस वीमेन्स कॉलेज में महाविद्यालयीन प्रचार्य के निर्देशन में एनुअल स्पोर्ट्स मीट-2024-25 के अंतर्गत विभिन्न खेलों के निर्णायक मैच का आयोजन, सम्पन्न हुआ। स्पोर्ट्स मीट के अंतर्गत महाविद्यालय में अध्येनरत छात्राओं में खेल प्रतिभा को विकसित करने के उद्देश्य से 5 दिसम्बर से महाविद्यालय के खेल मैदान में विभिन्न खेलों ने छात्राएं प्रतिभागी हुईं। फाइनल मैच का प्रारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सिस्टर शाता जोसेफ के द्वारा गेंद को उछालकर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल की भावना को जीवंत रखने का संदेश देते हुए कहा कि खेलों से शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जिससे कार्यक्षम विकसित होती है। आयोजन में बास्केटबॉल का फाइनल मैच बॉकॉम भाग दो व बीएससी भाग तीन, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, गणित, कंप्यूटर साइंस विषय की छात्राओं की बनी टीम के बीच खेला गया, जिसमें बीएससी भाग तीन की छात्राएं विजेता रही। खोखो का फाइनल मैच में बीएससी भाग दो गणित, कंप्यूटर साइंस विषय व बीएससी भाग दो बॉटनी विषय के बीच खेला गया, जिसमें बीएससी भाग दो की छात्राएं विजयी रहीं। हॉटबॉल का फाइनल मैच

होली क्रॉस वीमेन्स कॉलेज में एनुअल स्पोर्ट्स मीट संपन्न
छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन की तस्करी के मामले में गांधीनगर थाना पुलिस ने 01 आरोपी के पास से 80 नग प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन जप्त किया है। आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जप्त प्रतिबंधित इंजेक्शन की कीमत लगभग 50 हजार रुपये है। जानकारी के मुताबिक 13 दिसम्बर को थाना गांधीनगर पुलिस टीम पेट्रोलिंग में निकली थी, इस दौरान सतिंद्र विष्णु पुलिस पेट्रोलिंग वाहन को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम ने उसे घेराबंदी करके महुआपारा चर्च घाट बर्मा बाड़ी से पकड़ा और हाथ में रखे डोलो रखा इंजेक्शन बरामद किया। पृच्छाछ में आरोपी भूषण बेक 30 वर्ष निवासी महुआपारा थाना गांधीनगर संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। आरोपी के विरुद्ध धारा 22 (सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक मोरध्वज देशमुख, सहायक उप निरीक्षक राकेश मिश्रा, आरक्षक अतुल सिंह, बृजेश राय, अरविंद उपाध्याय, मनीष सिंह, ऋषभ सिंह सक्रिय रहे।



बीएससी भाग एक इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, गणित, कंप्यूटर साइंस विषय की छात्राओं व बीएससी भाग 3 बॉटनी विषय की छात्राओं की टीम के बीच खेला गया, जिसमें बीएससी भाग एक की छात्राएं विजेता रहीं। खेल आयोजन में स्कोर अंजना, मैच रेफरी विक्की विक्टर, कॉमिट्टीट एएसए अली रहे। मंच संचालन आलोक चक्रवर्ती ने किया। सभी खेल महाविद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षा अनुदेशक राधा खलखो के पर्यवेक्षण में संपादित हुआ। खेल आयोजन में महाविद्यालय की छात्राओं का उत्साह पूरी उर्जा से ओतप्रोत रहा। इस अवसर पर महाविद्यालय की उप प्राचार्य डॉ. सिस्टर मंजू टोपों सहित महाविद्यालय के सभी शिक्षक, कर्मचारी व छात्राओं की उपस्थिति रही।

प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ भाग रहे तस्कर को घेराबंदी करके पकड़ी पुलिस

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन की तस्करी के मामले में गांधीनगर थाना पुलिस ने 01 आरोपी के पास से 80 नग प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन जप्त किया है। आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जप्त प्रतिबंधित इंजेक्शन की कीमत लगभग 50 हजार रुपये है। जानकारी के मुताबिक 13 दिसम्बर को थाना गांधीनगर पुलिस टीम पेट्रोलिंग में निकली थी, इस दौरान सतिंद्र विष्णु पुलिस पेट्रोलिंग वाहन को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम ने उसे घेराबंदी करके महुआपारा चर्च घाट बर्मा बाड़ी से पकड़ा और हाथ में रखे डोलो रखा इंजेक्शन बरामद किया। पृच्छाछ में आरोपी भूषण बेक 30 वर्ष निवासी महुआपारा थाना गांधीनगर संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। आरोपी के विरुद्ध धारा 22 (सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक मोरध्वज देशमुख, सहायक उप निरीक्षक राकेश मिश्रा, आरक्षक अतुल सिंह, बृजेश राय, अरविंद उपाध्याय, मनीष सिंह, ऋषभ सिंह सक्रिय रहे।

प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन की तस्करी के मामले में गांधीनगर थाना पुलिस ने 01 आरोपी के पास से 80 नग प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन जप्त किया है। आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जप्त प्रतिबंधित इंजेक्शन की कीमत लगभग 50 हजार रुपये है। जानकारी के मुताबिक 13 दिसम्बर को थाना गांधीनगर पुलिस टीम पेट्रोलिंग में निकली थी, इस दौरान सतिंद्र विष्णु पुलिस पेट्रोलिंग वाहन को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम ने उसे घेराबंदी करके महुआपारा चर्च घाट बर्मा बाड़ी से पकड़ा और हाथ में रखे डोलो रखा इंजेक्शन बरामद किया। पृच्छाछ में आरोपी भूषण बेक 30 वर्ष निवासी महुआपारा थाना गांधीनगर संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। आरोपी के विरुद्ध धारा 22 (सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक मोरध्वज देशमुख, सहायक उप निरीक्षक राकेश मिश्रा, आरक्षक अतुल सिंह, बृजेश राय, अरविंद उपाध्याय, मनीष सिंह, ऋषभ सिंह सक्रिय रहे।



पॉलीटेक्निक कॉलेज विश्व एड्स दिवस पखवाड़ा के तहत विविध आयोजन

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वाधान में विश्व एड्स दिवस पखवाड़ा के तहत छात्र-छात्राओं को एचआईवी, एड्स के संबंध में मुख्य अतिथि डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता जिला नोडल अधिकारी एचआईवी, एड्स एवं क्षयरोग सरगुजा ने बताया। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी मंगल पाण्डेय एवं प्राचार्य अरजे पाण्डेय के अध्यक्षता में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। अतिथियों ने विश्व एड्स दिवस के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए विस्तार पूर्वक बीमारी से संबंधित जानकारी दी। प्राचार्य अरजे पाण्डेय ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि आज के कार्यक्रम को सार्थकता तब सिद्ध होगी जब हम सभी स्वयं जागरूक होंगे और अपने आस-पास के लोगों को एचआईवी, एड्स, क्षयरोग एवं यौन जनित रोग तथा नशे की लत से दूर रहने के लिए जागरूक करेंगे।

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वाधान में विश्व एड्स दिवस पखवाड़ा के तहत छात्र-छात्राओं को एचआईवी, एड्स के संबंध में मुख्य अतिथि डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता जिला नोडल अधिकारी एचआईवी, एड्स एवं क्षयरोग सरगुजा ने बताया। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी मंगल पाण्डेय एवं प्राचार्य अरजे पाण्डेय के अध्यक्षता में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। अतिथियों ने विश्व एड्स दिवस के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए विस्तार पूर्वक बीमारी से संबंधित जानकारी दी। प्राचार्य अरजे पाण्डेय ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि आज के कार्यक्रम को सार्थकता तब सिद्ध होगी जब हम सभी स्वयं जागरूक होंगे और अपने आस-पास के लोगों को एचआईवी, एड्स, क्षयरोग एवं यौन जनित रोग तथा नशे की लत से दूर रहने के लिए जागरूक करेंगे।